अमर उजाला

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 9 मई 2024

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जीवन में परमानंद की तलाश करें, वैसे तो जीने के एहसास में ही पर्याप्त आनंद है। -एमिली डिकिंसन

सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय व कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नील्सनआईक्यू की रिपोर्ट भारतीय परिवारों के व्यवहार के पैटर्न में घरेलू खर्चों व बचत को लेकर आ रहे बदलावों की झलक दिखाती हैं।

बचत और खर्च

सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के आंकड़ों को अगर कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नील्सनआईक्यू की दैनिक उत्पादों (एफएमसीजी) पर जारी तिमाही रिपोर्ट के साथ मिलाकर देखें, तो भारतीय परिवारों के व्यवहार के पैटर्न में घरेलू खर्चों व बचत को लेकर बदलावों की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। दरअसल, मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि देश में परिवारों की घरेलू बचत पिछले पांच वर्ष के निम्नतम स्तर पर तो पहुंची ही है, जीडीपी में बचत का हिस्सा भी पिछले 50 वर्षों में सबसे कम हो गया है, जो एक बड़ी समस्या को रेखांकित करता है। क्योंकि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत में गिरावट के आंकड़ों का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार, लोग अब बचत छोड़कर म्यूचुअल फंड, शेयरों व डिबेंचरों में निवेश कर रहे हैं, जो बाजार पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को तो दिखाता है, लेकिन पिछले तीन वर्ष में परिवारों का बैंक कर्ज जिस तरह से दोगुना हुआ है, उससे यही पता चलता है कि कर्ज लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति से लोग सहज हुए हैं, जो उनके आर्थिक व्यवहार में बड़े बदलाव का सूचक है। उल्लेखनीय है कि भारत दशकों से बचतकर्ताओं का राष्ट्र माना जाता रहा है। लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि, संयुक्त परिवारों में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी, जो लोगों की क्रय क्षमता को प्रभावित करती है और आसान किस्तों में कर्ज मुहैया होने से भी यह प्रवृत्ति तेजी से बदल रही है। कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर इसका उपयोग संपत्ति खरीदने या अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा हो। कोविड के बाद लॉकडाउन के दौर की परिस्थितियां गवाह हैं कि लंबे समय तक चलने वाले कर्ज की किस्तें किस तरह लोगों की कमर तोड़ सकती हैं। नहीं भूलना चाहिए कि 2008 की वैश्विक मंदी से भारत के अप्रभावित रहने की बड़ी वजह भारतीयों की बचत की प्रवृत्ति ही थी। दूसरी तरफ, नील्सनआईक्यू की रिपोर्ट का यह कहना कि उपभोक्ता वस्तुओं की खपत के मामले में बीती तिमाही में गांवों ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है, दर्शाता है कि अब उपभोक्तावाद गांवों तक पहुंचने लगा है। इससे एनएसओ की हालिया रिपोर्ट के निष्कर्षों की ही पुष्टि होती है, जिनके अनुसार, न सिर्फ शहरों में, बल्कि गांवों में भी लोग वित्तीय रूप से समृद्ध हो रहे हैं, जिससे खपत व खर्च दोनों बढ़े हैं। कुल मिलाकर, व्यक्तिगत समृद्धि व निवेश का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, पर घरेलू बचत की अपनी भारतीय परंपरा रही है, जिसे अनदेखा कर कर्ज लेकर वस्तुएं जुटाने की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

संसाधनों पर निजी अधिकारों का पेच

भारत में जब मूल अधिकारों की प्रेरणा ली गई, तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को एक साथ रखा गया और संपत्ति के अधिकार को सामुदायिक बनाया गया था। लेकिन संसाधनों या संपत्ति पर अधिकार समुदाय का है या फिर निजी व्यक्ति का-यह प्रश्न एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है।

हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्रकृति से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार सर्वोपरि हैं। इन निजी अधिकारों की रक्षा करना प्रकृति के नियमों की रक्षा करना है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का मूल तत्व भी है। इस सामान्य नियम पर अक्सर विवाद होते रहे हैं कि भारत जैसे देश में संसाधनों या संपत्ति पर अधिकार समुदाय का है या फिर निजी व्यक्ति का। ऐसा ही प्रश्न एक बार फिर न्यायालय के समक्ष लाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) तथा (सी) के प्रावधानों की व्याख्या नौ-न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की जाएगी, जो स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक होगी।

सीबीपी श्रीवास्तव

अध्यक्ष, सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली

लेकिन पहले इस विषय को समझ लेना जरूरी है। गौरतलब है कि कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी, 1978 मामले में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने कहा था कि संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व की संकल्पना में सभी प्राकृतिक व भौतिक संसाधन तथा सार्वजनिक और निजी संसाधन शामिल होंगे। प्रश्न यह है कि यदि निजी संसाधनों पर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो आज की आर्थिक रूप से उदारीकृत व्यवस्था में जब निजी निवेश जरूरी हो गया है, तो हम निवेशकों को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? इस पर विचार करने से पहले यह देखना जरूरी है कि संविधान निर्माताओं ने सार्वजनिक और निजी अधिकारों को किस प्रकार संतुलित किया है और वर्तमान परिदृश्य में उसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए।

मूल संविधान में उदारवादी और समाजवादी, दोनों ही विचारों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के साथ आवश्यकतानुसार संसाधनों के वितरण पर समान बल है। यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए वह शासन व्यवस्था को निर्देश देता है, ताकि लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति कर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। हालांकि हमने

समाजवादी विचारों को शामिल करने की प्रेरणा सोवियत संघ से ली है, लेकिन भारतीय समाजवाद अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इसमें उदारवादी गुणों का मिश्रण है। इसका अर्थ यह है कि संविधान संसाधनों का आवश्यकतानुसार वितरण कर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करता है।

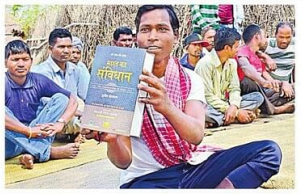

इसी कारण अनुच्छेद 39(बी) और (सी) में क्रमशः भौतिक संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के कुछ लोगों के पास इकट्ठा होने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इन्हीं समाजवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पहले संशोधन अधिनियम 1951 से अनुच्छेद 31 ए, 31 बी और नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और उसके वितरण का प्रावधान करने के लिए भूमि सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई थी। इसी प्रकार, 25वें संशोधन से अनुच्छेद 31सी जोड़कर भूमि सुधार संबंधी निदेशक तत्वों, विशेष कर अनुच्छेद 39(बी) और (सी) को संरक्षण दिया गया है।

दूसरी ओर, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत व्यक्तियों को संपत्ति का मूल अधिकार देकर उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। यानी व्यक्ति के निजी अधिकारों को भी समान महत्व दिया गया था। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम से संविधान की उद्देशिका में 'समाजवादी' शब्द जोड़े जाने के बाद उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी सिद्धांतों के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि समाजवादी देशों में संपत्ति पर निजी अधिकारों को वरीयता नहीं दी जा सकती है। इसी कारण, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से इसे मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि राज्य विधि के तहत निजी संपत्ति का नियमन कर सके। पर इसका मतलब यह नहीं है कि देश में लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है और राज्य समुदाय के स्वामित्व के नाम पर उसका अधिग्रहण नहीं कर सकता है, जब तक कि संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। ऐसी व्यवस्था जन कल्याण के उद्देश्य से की गई है। आज जब आर्थिक विकास में निजी निवेश की भूमिका अपरिहार्य हो गई है, इसके बिना जन कल्याण की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

भारत के संविधान में लोकतंत्र को सर्वोपरि माना गया है और संसाधनों का वितरण अर्थात समाजवादी सिद्धांत उसकी प्राप्ति के साधन हैं। इसके अलावा, संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार भी है, जिसके कारण इसका मूल तत्व नैसर्गिक न्याय है। भारत में जब मूल अधिकारों की प्रेरणा ली गई, तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को एक साथ रखा गया और संपत्ति के अधिकार को सामुदायिक बनाया गया था। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां संसाधनों पर निजी अधिकारों का महत्व कम है और इन्हें छीना जा सकता है।

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लोकतांत्रिक है तथा निजी अधिकारों व समाजवादी सिद्धांतों के बीच इसमें संतुलन है। बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार के बाद राज्य, बाजार और नागरिक समाज, सभी हितधारकों द्वारा एक साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों की उदारवादी व्याख्या जरूरी है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 39(बी) में उल्लिखित समुदाय के स्वामित्व वाले प्रावधानों को भी समझा जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थिति में यदि निजी अधिकारों को केवल इस आधार पर निर्बंधित किया गया कि संसाधनों में निजी संपत्ति भी शामिल है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा।

संविधान में संपत्ति का अर्थ मुख्यतः भूमि संसाधन है, क्योंकि अनुच्छेद 39(सी) में उल्लिखित शब्द 'उत्पादन के साधन' में मुख्यतः भूमि और पूंजी शामिल हैं, जिनके जमा होने पर रोक लगाई गई है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 31सी में भूमि सुधार संबंधी निदेशक तत्वों को अधिकारों पर वरीयता देने का अर्थ निजी अधिकारों को छीनना नहीं है। वस्तुतः अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अतः संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व की व्याख्या कर निजी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

दलाई लामा

हमारे जीवन में सबसे सुखमय और मूल्यवान वही क्षण होते हैं, जब हम भौतिक जगत के मायाजाल से दूर आत्मानुभूति में पूर्णरूप से स्थित हो जाते हैं। ऐसा सौभाग्य तभी मिलता है, जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं।

अंततः दरिद्र ही बनाती है सांसारिक समृद्धि की भूख

धनी होना एक कला है। इसका रहस्य अकिंचन बनने में छिपा है। अकिंचन होने पर ही हम सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। हमारे जीवन में सबसे अधिक सुखमय और मूल्यवान वही क्षण होते हैं, जब हम भौतिक जगत के मायाजाल से अपने आप को तटस्थ करके आत्मानुभूति में पूर्णरूप से स्थित हो जाते हैं। इन क्षणों को प्राप्त करने का सौभाग्य तभी मिलता है, जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं। भौतिक जगत की संपत्ति इस दिव्य सौंदर्य को खरीद नहीं सकती। यही वे क्षण होते हैं, जब आत्मा ईश्वर की अनुपम सुंदरता का पूजन करती है। मनुष्य का सर्वोत्तम सुखमय क्षण ही उसका सबसे मूल्यवान समय होता है। मानव अनुभूति की पराकाष्ठा अपनों पर शासन करने की अथवा संसार में किसी भी इच्छित, मूल्यवान निधि को खरीदने की शक्ति में नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो आत्मा की अनुभूति से मिल पाती है। सुख की यही व्यावहारिक मुद्रा 'प्रेम' है।

सबसे अधिक धनी वही है, जो सबसे अधिक देता है। लेकिन ऐसा देना सांसारिक धन के रूप में कदापि नहीं हो सकता। रुपया, आना, पाई तो केवल प्रतीक मात्र हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। जीवन के सुखद क्षणों में तो इनका प्रवेश ही नहीं होता। इसलिए जिस संसार में हम चलते-फिरते और बसते हैं, उसके वास्तविक रूप को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। साधारण मनुष्य की दृष्टि केवल नाशवान वस्तुओं तक ही सीमित रहती है। पर इस ऊपरी स्थूलता के पीछे बहुमूल्य आध्यात्मिक वस्तुओं का एक अनादि सागर भी है, जिसके बारे में हममें से ज्यादातर अनजान हैं। यह आध्यात्मिक सागर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसके लिए किसी का धनी या दरिद्र होना जरूरी नहीं। इस संपत्ति पर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस संसार में हमारा जन्म भी इसी की प्राप्ति के लिए हुआ है। यदि हम इस अध्यात्म की खोज में तत्पर नहीं होते हैं, तो हमारा जीवन नीरस और निरर्थक बन जाता है।

जो मनुष्य सांसारिक समृद्धि से संतुष्ट होने की कल्पना करता है, सच्चे अर्थों में वह दरिद्रता की ओर ही बढ़ता है। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है, जब वह अपने क्षुद्र व्यावहारिक क्षेत्र के दायरे के बाहर कुछ भी नहीं देख पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि आत्मशक्ति के बिना ये इंद्रियां केवल मुद्रा हैं। ऐसे जीवन-व्यापार में वह केवल अपनी आत्मा का हनन करता है। पर जो उस अनुपम दिव्य सौंदर्य को अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि समझ कर अपनी आत्मा की मौन प्रेरणा का अनुकरण करता है, वह निश्चित रूप से एक न एक दिन इस पृथ्वी और इसकी समृद्धि का मालिक बन जाता है। जीवन की अमूल्य निधि एक स्रोत के समान स्वतः हमारे भीतर से फूट पड़ती है। आध्यात्मिक-व्यापार की एकमात्र मुद्रा प्रेम है। यह सांसारिक व्यवहार के ठीक उलट है। आध्यात्मिक सभ्यता भौतिक सभ्यता के विपरीत होती है।

अध्यात्म में ही असली आनंद...

सूत्र

आध्यात्मिक सागर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसका आनंद लेने के लिए अमीर या गरीब होना जरूरी नहीं। इस पर तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस संसार में हमारा जन्म भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। यदि हम इस अध्यात्म की खोज में तत्पर नहीं होते हैं, तो हमारा जीवन नीरस और निरर्थक बन जाता है।

दूसरा पहलू

विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका को सबसे असमान देश बताया है, जहां 71 प्रतिशत संसाधनों पर 10 फीसदी लोगों का कब्जा है।

कितने सुखी हैं दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत

तीस साल पहले दक्षिण अफ्रीका के मतदाताओं ने रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला को चुनकर इतिहास रचा था। आज दक्षिण अफ्रीका में सभी नस्लों के लोग साथ बैठकर खाते हैं। समलैंगिकों के अधिकारों को ज्यादातर लागू किया गया है, वहां का प्रेस आजाद है तथा विरोध व राजनीतिक बहस जीवन का हिस्सा हैं।

पर अब भी अमीरों और गरीबों के बीच खाई है, बिजली-पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की सेवा ध्वस्त हो चुकी है, तथा दूरस्थ इलाकों में अश्वेत समुदाय अलग-थलग पड़े हैं। देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 81 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें आर्थिक आजादी नहीं मिली। रंगभेदी दौर में जो आर्थिक बाड़ेबंदी लागू की गई थी, वह अब भी बरकरार है। विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका को दुनिया का सबसे असमान देश बताया है, जहां 71 प्रतिशत संसाधनों पर 10 फीसदी लोगों का कब्जा है, जबकि नीचे की 60 प्रतिशत आबादी के पास सिर्फ सात फीसदी संपत्ति है।

जॉन एलिगन

नेल्सन मंडेला ने 30 फीसदी खेती की जमीन अश्वेतों को देने का वादा किया था। लेकिन अब भी सिर्फ 25 फीसदी श्वेतों ने अपनी जमीन अश्वेतों को दी है।

जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से मात्र 29 फीसदी कंपनियों में अश्वेतों की हिस्सेदारी है, पर इनमें से एक भी कंपनी का पूर्ण स्वामित्व किसी अश्वेत के पास नहीं है। अश्वेत समुदाय को खनन क्षेत्र में ज्यादा हिस्सेदारी मिली है, जहां अश्वेत स्वामित्व पिछले दो दशक में दो फीसदी से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। पर इसका लाभ इस समुदाय के ज्यादा लोगों को नहीं मिला है।

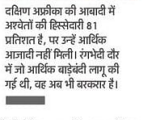

दक्षिण अफ्रीका की आबादी में अश्वेतों की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत है, पर उन्हें आर्थिक आजादी नहीं मिली। रंगभेदी दौर में जो आर्थिक बाड़ेबंदी लागू की गई थी, वह अब भी बरकरार है।

रंगभेद शासन के अंत के समय दक्षिण अफ्रीका में खेती की पूरी जमीन पर श्वेतों का कब्जा था। सत्ता में आने पर मंडेला ने कुछ वर्षों में 30 फीसदी खेती की जमीन अश्वेतों को देने का वादा किया था। लेकिन इतने समय बाद सिर्फ 25 फीसदी श्वेतों ने अपनी जमीन अश्वेतों को दी है। दक्षिण अफ्रीका की आबादी में श्वेतों की हिस्सेदारी मात्र सात फीसदी है, पर कृषि भूमि के करीब आधे पर अभी तक उनका कब्जा है। हालांकि लोकतंत्र आने के बाद गरीबी घटी है, लेकिन अब भी हर तीन अश्वेतों में से दो 80 डॉलर मासिक पर गुजारा करते हैं। सभी अश्वेतों को घर देने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अनेक अश्वेतों को वैसी जगह सरकारी आवास मिले हैं, जहां रोजगार की सुविधा नहीं है। अब भी उन्हें उस बदलाव की उम्मीद है, जिसका सपना उन्होंने देखा था।

-साथ में लिनसे च्यूटल, लॉरेन लिथरबी और जोओ सिल्वा।

©The New York Times 2024

आंकड़े

शहरी आबादी

कई देशों में 92 फीसदी आबादी शहरों में रहती है, पर भारत में 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 36 फीसदी आबादी ही शहरों में रहती है।

स्रोत: UNPD

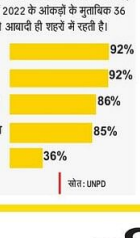

हर पुरुष को महिलाओं को सम्मान के भाव से देखना चाहिए। जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है।

सच्चा पुरुषार्थ

अंतर्यात्रा
संकलित

स्वामी विवेकानंद के भाषण से भारत के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी भी प्रभावित थे। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। एक विदेशी महिला उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने स्वामी जी से बिना किसी संकोच के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हैं?

उस विदेशी महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। आप बड़े ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसलिए मैं आपसे शादी करना चाह रही हूं।

स्वामी ने महिला से विनम्रता से कहा कि एक संन्यासी होने के कारण मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। महिला ने पूछा कि वह कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और आपको मैं मां मान लेता हूं। ऐसा करने से आपको मेरे जैसा ही बेटा मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों पर गिर गई। उन्होंने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे आप पर गर्व है। असली पुरुषार्थ वही होता है, जब पुरुष के मन में नारी के लिए मां जैसा सम्मान का भाव होता है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 अक्तूबर, 1992

ओडिशा के कांग्रेस नेताओं के निष्कासन पर रोक

उड़ीसा के इंका नेताओं के निष्कासन पर रोक

नई दिल्ली, ३० अक्टूबर (भाषा)। उड़ीसा के पांच वरिष्ठ कांग्रेस (इ) नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में जारी निष्कासन आदेश पर रोक लगा दी गयी है और यह मामला पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को सौंप दिया गया है।

पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष पी.वी.नरसिंह राव के हस्तक्षेप के कारण ऐसा किया गया है। तीन पूर्व मंत्रियों दोल गोविन्द प्रधान, युधिष्ठिर जेना और नेत्रानंद मलिक सहित पार्टी के पांच वरिष्ठ नेताओं को उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जानकी बल्लभ पटनायक ने गत सात अक्टूबर १९९२ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

ओडिशा के पांच वरिष्ठ कांग्रेस (इ) नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में जारी निष्कासन आदेश पर रोक लगा दी गई है और उनका मामला अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को सौंप दिया गया है।

पहिए सांसों को रौंद रहे हैं

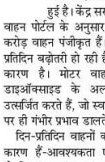

सड़कों पर वाहनों की बेलगाम भीड़ और एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ के चलते वायु प्रदूषण के साथ-साथ सड़क हादसे भी होते रहते हैं।

अतुल अग्रवाल | परिवहन

भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते मोटर वाहनों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, आज देश में लगभग 37 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। वाहनों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। मोटर वाहन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जो स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी, दोनों पर ही गंभीर प्रभाव डालते हैं।

दिन-प्रतिदिन वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी के दो कारण हैं-आवश्यकता एवं महत्वाकांक्षा। ज्यादातर दोपहिया वाहन 'आवश्यकता', तो कई चौपहिया वाहन 'महत्वाकांक्षा' पूरी करने के लिए खरीदे जाते हैं। चौपहिया वाहन अधिकतर सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं, ताकि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। जिन लोगों के पास पहले से चौपहिया वाहन मौजूद हैं, वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ाने के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। इस तरह परिवार के हरेक सदस्य के पास अपना चौपहिया वाहन होता है, जिन्हें वे बिना पुल किए सड़क पर चलाते हैं। सड़क पर वाहनों की सघनता और भीड़ बढ़ाने में ऐसे लोगों का प्रमुख योगदान होता है।

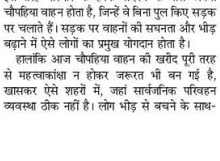

हालांकि आज चौपहिया वाहन की खरीद पूरी तरह से महत्वाकांक्षा न होकर जरूरत भी बन गई है, खासकर ऐसे शहरों में, जहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग भीड़ से बचने के साथ-साथ अपना समय भी बचाना चाहते हैं। बहरहाल, सड़कों पर आज हर जगह जाम है और इस समस्या ने छोटे शहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हर तरफ वाहनों का धुआं एवं शोर है।

सभी सरकारें चाहती हैं कि वाहनों की बिक्री साल दर साल बढ़ती रहे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी को जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बढ़ते वाहनों से न सिर्फ हमारी सड़कें संकरी प्रतीत होती हैं, बल्कि सड़कों को चौड़ा करने तथा वैकल्पिक मार्ग व फ्लाईओवर इत्यादि बनाने का आर्थिक बोझ भी बढ़ने लगता है और फिर एक दिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण ये वैकल्पिक मार्ग एवं फ्लाईओवर भी नाकाफी हो जाते हैं।

सड़कों पर वाहनों की बेलगाम भीड़ और एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ के चलते सड़क हादसे भी होते रहते हैं। ये वाहन पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा बनते हैं। वर्ष 2022 में ही कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,68,491 लोगों की जानें गईं एवं 4,43,366 लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लगभग 67 फीसदी लोग 18-45 आयु वर्ग के थे, जबकि लगभग 84 फीसदी लोग 18 से 60 वर्ष की उम्र के कामकाजी लोग थे।

हालांकि आजकल विद्युतीय वाहनों की चर्चा हो रही है। ऐसे वाहनों से वायु प्रदूषण से कुछ हद तक राहत तो जरूर मिल सकती है, परंतु सड़कों पर सघन यातायात से नहीं। ऐसा ही हाइड्रोजन आधारित वाहनों के लिए भी कहा जा सकता है।

ऐसे में सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम करने के क्या उपाय हैं? इसके लिए हम छोटी-छोटी दूरी पैदल या साइकिल से तय कर सकते हैं। अपना वाहन पूल कर सकते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक यातायात प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के साथ हमें प्रकृति एवं आगामी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के बारे में भी सोचने की जरूरत है। बढ़ते वैश्विक तापमान को देखते हुए हमें स्वयं जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उपाय करने होंगे।

सरकार एवं नीति निर्माताओं को भी वाहनों की अंधाधुंध बिक्री एवं खरीद को विनियमित करने की जरूरत है। प्रत्येक परिवार के लिए जरूरत के हिसाब से एक या दो वाहनों को खरीदने की सीमा तय की जा सकती है। हालांकि इस बारे में सभी हितधारकों से सुझाव मांगकर विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होगी। इसके अलावा, बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' को सुदृढ़ करने पर जोर देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों के निर्माण पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन सिर्फ सड़कें बिछाने से काम नहीं होगा। जरूरत है, उन सड़कों को सुरक्षित बनाने एवं नियमित परिवहन व्यवस्था चलाने की। अगर जल परिवहन के विकास पर जोर दिया जाए, तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

कठघरे में टीके

कोरोना के टीके कोविशील्ड को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो यह स्वाभाविक ही है। इस टीके की निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने टीकों को वापस लेने की पहल की है। खासकर, टीके वैक्सजेवरिया पर सुरक्षा चिंताओं के बीच कंपनी की पहल को अलग-अलग नजरिये से देखा जा रहा है। यह कंपनी अपने टीकों की शिकायतों से परेशान है और टीके को वापस लेने से जहां उसकी चिंता घटेगी, वहीं दूसरी ओर, लोगों की शिकायतों में भी इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोविशील्ड के दुर्लभ दुष्प्रभावों पर सुनवाई करने वाला है। हालांकि, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है, पर यह बड़ी बात है कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है और इसमें शीर्ष अदालत से प्रभावित नागरिकों के लिए वैक्सीन क्षति भुगतान व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर मंजूर कर लिया, तो केंद्र सरकार को भारत में भी टीका दुष्प्रभाव क्षतिपूर्ति तंत्र बनाना पड़ेगा।

महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान के चलते गंभीर रूप से अक्षम हुए लोगों की खोज होनी चाहिए और एक विस्तृत सूची बननी चाहिए। हालांकि, यह काम आसान नहीं है। ध्यान देने की बात है, कोरोना पीड़ितों या मृतकों के परिजन को मुआवजा देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया था। ऐसे बच्चों के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे, जो कोरोना के समय अनाथ हो गए थे। अब अगर टीकों के दुष्प्रभावों से पीड़ित लोगों या मृतकों को मुआवजा मिलता है, तो यह एक कल्याणकारी राज्य (भारत) के लिए सकारात्मक फैसला होगा। भारतीयों को सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि देश या क्षेत्र के हिसाब से एस्ट्राजेनेका पक्षपात करने लगे। अगर यूरोप में मुआवजा दिया जाता है, तो एशिया या भारत में क्यों नहीं? ध्यान देने की बात है, भारत में लोगों को कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में भी एस्ट्राजेनेका की टीका संबंधी स्वीकारोक्ति के बाद चिंता का आलम है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि टीके से रक्त का थक्का जमने का खतरा है और इस वजह से ब्रिटेन में कंपनी को मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

दवा कंपनी अब टीके वापस ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर मंजूर कर लिया, तो केंद्र सरकार को भारत में भी टीका दुष्प्रभाव क्षति पूर्ति तंत्र बनाना पड़ेगा।

वैसे, कंपनी अभी भी अपने दामन को पाक-साफ बताने में लगी हुई है और वह यूरोप में लग रहे आरोपों को तभी स्वीकार करेगी, जब कोई विशेषज्ञ गवाही देगा। विशेषज्ञ चिकित्सक की गवाही का यूरोप में बड़ा महत्व होता है, तो भारत में भी कम नहीं होता। जहां भी दुष्प्रभाव के मामले आते हैं, वहां चिकित्सकों को अपनी योग्यता का परिचय देना होगा। टीके की कमियों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था के भविष्य के लिए यह जरूरी है कि सेवा में कमियों को दोहराया न जाए। टीका बेचकर भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनी को भी सच्चाई के पक्ष में दिखना होगा। हालांकि, फिलहाल कंपनी इस पूरी शिकायत को घटाकर देख रही है। उसने संकेत यही किया है कि बाजार में उपलब्ध टीकों की अधिकता और मांग में कमी की वजह से टीकों को वापस लिया जा रहा है। खैर, बाजार से टीके वापस लिए जा सकते हैं, पर जिन दुर्लभ मामलों में टीके की खुराक ने शरीर के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपायी कैसे हो सकती है? इंतजार कीजिए, हमारी दुनिया उस ओर बढ़ रही है।

चुनाव में चंद सूबे कर देंगे फैसला

यहां स्कैन करें

नारायण रामचंद्रन | वित्त विशेषज्ञ व उद्यमी

कुछ राज्य हैं, जहां लगभग आधे क्षेत्रों में हार-जीत का अंतर बहुत कम रहेगा और इसी से तय होगा कि एक दल के बहुमत वाली सरकारों की प्रवृत्ति बनी रहती है या उलट जाती है।

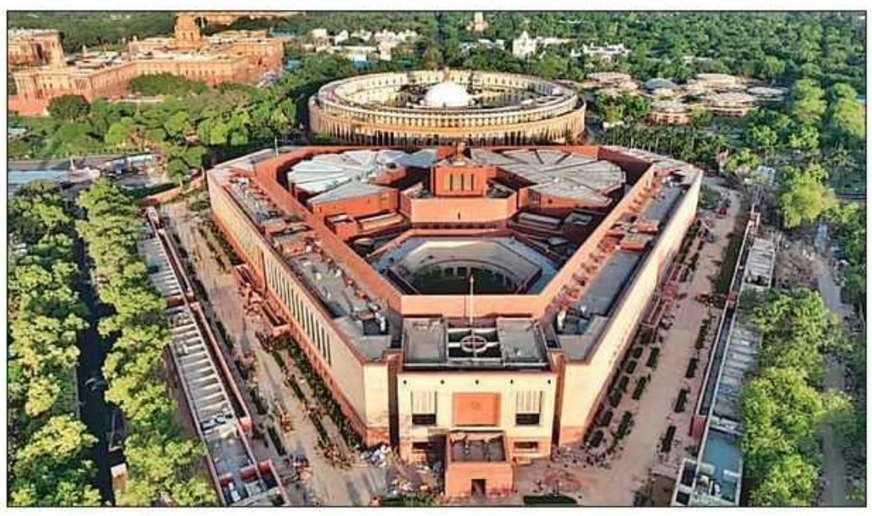

भारत 18वीं लोकसभा के चुनाव के बीच पहुंच गया है। आजादी के बाद हुए पहले आठ लोकसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से ज्यादा सीटें हुआ करती थीं। साल 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत से 22 सीटें ज्यादा मिली थीं, जबकि साल 1984 में कांग्रेस के ही राजीव गांधी की झोली में बहुमत से 143 सीटें ज्यादा आई थीं।

वैसे, कुल लोकसभा सीटों की संख्या भी समय के साथ बदलती रही है, साल 1951 में हुए पहले चुनाव के लिए 489 के निचले स्तर से लेकर वर्तमान 543 सीटों तक। साल 2009 में नौवें से लेकर 15वें आम चुनाव तक, जीतने वाली पार्टी बहुमत से दूर रही थी, साल 2004 में मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस के पास बहुमत से 127 सीटें कम थीं, जबकि साल 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस के पास बहुमत से 24 सीटें कम थीं। किसी एक पार्टी के पास अगर बहुमत न हो, तो जाहिर है, गठबंधन सरकारों की जरूरत पड़ती है। खैर, साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में प्रारूप बदल गया, जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से क्रमशः 10 और 31 सीटें ज्यादा हासिल हुईं।

अब लोकसभा चुनाव 2024 में क्या भाजपा या कांग्रेस संसद में बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली किसी एक पार्टी की परंपरा को बरकरार रखेगी? बहुमत के लिए जरूरी सीटों से ज्यादा सीटें पाने का कारनामा यही दो पार्टियां कर सकती हैं, क्योंकि केवल यही दो हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा उम्मीदवारों ने 446 निर्वाचन क्षेत्रों में और कांग्रेस नेताओं ने 327 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण कराया है। सांख्यिकीय रूप से अगर देखें, तो अकेले दम पर कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 82 प्रतिशत सीटें जीतनी होंगी। ऐसे में, फिलहाल कांग्रेस के लिए अकेले दम पर बहुमत से आधी सीटें भी जीतने की संभावना कम लगती है। उम्मीदवारों के मामले में इस समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा है, जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची की घोषणा नहीं की है, बहु-चरणीय चुनाव में राजनीतिक दलों को यह सुविधा मिलती है।

दुनिया भर में अनेक प्रकार की मतदान प्रणालियां हैं। ब्रिटेन की तरह ही भारत 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम' (एफपीटीपी) का इस्तेमाल करता है। यह शब्द घुड़दौड़ के संदर्भ में आता है, जहां पोस्ट या विजय रेखा को पार करने वाला पहला घोड़ा एकमात्र विजेता होता है, चाहे वह सिर्फ नाक भर आगे रहा हो या मील भर आगे। सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीतता है, भले ही उस व्यक्ति का मत प्रतिशत डाले गए कुल मतों के आधे से भी कम हो और ऐसा अक्सर होता है, जब मैदान में दो से ज्यादा उम्मीदवार उतरते हैं।

साल 2019 के चुनावों में 224 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता हिस्सेदारी के साथ जीत हासिल हुई थी। इन 224 सीटों में से ज्यादातर पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हासिल हुई थीं। इन पांच राज्यों में कुल मिलाकर 200 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। गुजरात को छोड़ दीजिए, तो शेष राज्यों में इस बार भाजपा अपेक्षाकृत कम जोर लगा रही है, उसका चुनावी अभियान महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में ज्यादा जोर-शोर से चला है।

दूसरी ओर, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, गैर-भाजपा दलों ने कुल 117 निर्वाचन क्षेत्रों में आधे से अधिक वोट हासिल किए थे, जिनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सीटें शामिल थीं।

इन चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी करने का एक तरीका यह है कि भाजपा को उसकी 224 सुरक्षित सीटें दे दी जाएं और गैर-भाजपा दल अपनी 117 मजबूत सीटें ले लें। शेष 202 निर्वाचन क्षेत्रों को विश्लेषण में 'स्विंग सीट' के रूप में गिना जाए। वैसे, ऐसे विश्लेषण के दो कारणों से गलत परिणाम हो सकते हैं। एक, जरूरी नहीं कि पिछले चुनाव का इतिहास दोहराया जाए। दूसरा, राज्य स्तर पर सियासी समर्थन या विरोध की स्थिति कुछ राज्यों में बदली हुई दिखती है। मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में सपा और बसपा के बीच का गठबंधन टूट गया है और सपा ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। बिहार में नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) को एनडीए में 16 सीटें आवंटित की गई हैं और यह कहना अभी मुश्किल है कि इस बार नतीजे क्या आने वाले हैं। महाराष्ट्र में देखें, तो अब वहां पर दो शिवसेना और दो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं। इस बात पर गरमागरम बहस चल रही है कि मतदाता महाराष्ट्र में किसे पसंद करेंगे। पार्टियों के मूल संस्करण लोगों को पसंद आएंगे या नए संस्करणों को ज्यादा वोट मिलेंगे?

बहरहाल, हर सीट का अपना महत्व है और यह मायने नहीं रखता कि सीट किस राज्य से आ रही है। 17 राज्य ऐसे हैं, जहां 10 से अधिक लोकसभा सीटें हैं, सीटें कुल मिलाकर, 502 हो जाती हैं। तमाम राज्यों के बीच छह को 'स्विंग' राज्य के रूप में गिना जाता है। ये राज्य हैं- महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ व हरियाणा। आप 2024 के लिए बिहार को इस सूची में जोड़ सकते हैं। ये असल युद्धभूमि हैं। वैसे, ये अमेरिकी अर्थों में 'स्विंग स्टेट्स' नहीं हैं, क्योंकि ये राज्य एक अकेले विजेता के खाते में नहीं जाते हैं और यहां अनेक सीटों पर जीत-हार का फैसला वोट के कम अंतर से होता है।

उम्मीदवारों के साथ-साथ स्थानीय कारक भी हार-जीत में काम करते हैं। इन छह 'स्विंग' राज्यों में कुल 152 सीटें हैं और बिहार को जोड़ दें, तो 192 सीटें हैं। मेरे अनुमान के अनुसार, इनमें से लगभग आधे क्षेत्रों में हार-जीत का अंतर बहुत कम रहेगा और इसी हार-जीत से यह तय होगा कि एक दल के बहुमत वाली सरकारों की हालिया प्रवृत्ति कायम रहती है या उलट जाती है। मुमकिन है, अनेक सीटों पर बहुत मामूली अंतर से पलड़ा इधर या उधर झुक जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विमान सेवाओं पर आए दिन मंडराते संकट के बादल

यहां स्कैन करें

सरस चंद्र त्रिपाठी | पूर्व मेजर व विमानन विशेषज्ञ

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब विस्तारा एयरलाइन की एक के बाद दूसरी उड़ानें रद्द हो रही थीं। अब एअर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से अधिक उड़ानें इसलिए रोकनी पड़ीं, क्योंकि मंगलवार की देर रात से उसके क्रू मेंबर अचानक 'बीमार' हो गए। यह बीमारी दरअसल विरोध जताने का उनका एक तरीका है। वे एअर इंडिया एक्सप्रेस और एअर इंडिया के विलय के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे उनके वेतन-भत्ते पर व्यापक असर पड़ सकता है। विस्तारा के साथ भी यही मामला था, एअर इंडिया के साथ उसके विलय को लेकर आपत्तियां हैं। हालांकि, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 'ऑपरेशनल कारणों से' सेवाएं रद्द होने की बात कही है।

असल में, जब से टाटा समूह ने एअर इंडिया को अपने अधीन लिया है, तब से किसी न किसी वजह से यह समूह सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में घरेलू ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। इस प्रकार जब अचानक उड़ानें रद्द होती हैं, तो अनेक लोगों की नौकरियों पर बन आ सकती हैं, कुछ लोगों तक जरूरी इलाज नहीं पहुंच सकता है और कुछ मनोरंजन या अपने अन्य उद्देश्यों से दूर हो सकते हैं। यानी, जीवन-मरण के प्रश्नों से लेकर पर्यटन शादी, नौकरी तक के मामले इससे जुड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि उड़ानों का रद्द होना निजी ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी नुकसानदेह होता है।

पायलटों, सहायक स्टाफ की कमी, सीमित बुनियादी ढांचे आदि के कारण देश की ज्यादातर बड़ी विमानन कंपनियां तनाव में काम कर रही हैं।

संगठनात्मक दृष्टि से टाटा समूह के पास इस समय चार एयरलाइंस हैं, जिनमें एअर इंडिया को उसने भारत सरकार से खरीदा है। इसके अलावा, उसके पास विस्तारा, एअर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट (एअर एशिया) है। टाटा ने इन चारों सेवाओं के आपस में विलय की योजना बनाई है, लेकिन कर्मचारियों, पायलटों व उनकी यूनियनों के साथ प्रबंधन के टकराव के कारण यह कार्य काफी कठिन होता जा रहा है। इसमें विस्तारा एयरलाइन को प्रीमियम सेवा माना जाता है और उसके कर्मियों का वेतन काफी अच्छा है। जबकि, एअर एशिया की हालत काफी खराब है, इसलिए उसके कर्मियों के वेतन-भत्ते काफी कम हैं। दिक्कत यह है कि जब कंपनियों का विलय होता है, तो तमाम स्तरों पर समानता का प्रयास किया जाता है। टाटा की मुश्किलों की यही जड़ है। जिनको ऊंचा वेतन मिलता है, उनको वेतन-कटौती का डर सता रहा है, इसलिए विरोध की आवाजें उठ रही हैं। विमानन कंपनी और सरकार इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे किसी घटनाक्रम में यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां इसके उलट ही हो रहा है। ऐसे में, कोई यात्री आखिर क्या करे? इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मसलन, यदि दो घंटे के अंदर यात्री चाहे, तो दूसरी फ्लाइट में अपने गंतव्य के लिए टिकट ले सकता है। इसी तरह, विमानन कंपनी का भी यह फर्ज है कि वह अगली फ्लाइट में यात्री को जगह देने का प्रयास करे। दूसरा, यदि यह संभव नहीं है, तो यात्रियों के लिए भोजन-ठहरने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और किसी दूसरी फ्लाइट से जल्द ही उनको गंतव्य की ओर भेजना चाहिए या पैसे रिफंड का विकल्प उनको देना चाहिए। यदि यात्री रिफंड लेता है, तो उसे दोगुना रिफंड का प्रावधान है, इसलिए अधिकांश विमानन कंपनियां यात्रियों को किसी दूसरे विमान से ही भेजने का प्रयास करती हैं।

ताजा घटनाक्रम बताता है कि भारत में विमानन उद्योग अब भी परिपक्व नहीं हो सका है। ऐसे सामूहिक रूप से 'बीमार' हो जाने के विरुद्ध सरकार को कानून बनाना चाहिए। पायलटों, बैकअप स्टाफ की कम संख्या, सीमित बुनियादी ढांचे आदि के कारण भारत की ज्यादातर बड़ी विमानन कंपनियां तनाव में काम कर रही हैं, जिस कारण उड़ानों के अचानक रद्द होने या उनमें अघोषित देरी जैसी समस्याओं से यात्री जूझते रहते हैं। यह स्थिति तब और गंभीर नजर आती है, जब आंकड़े बताते हैं कि देश की शीर्ष पांच विमानन कंपनियों में से चार हर साल करोड़ों रुपये का घाटा सह रही हैं। इसका अर्थ है कि पूरे विमानन उद्योग में ही व्यापक सुधार की तरफ हमें बढ़ना होगा। उड्डयन क्षेत्र में विश्व स्तरीय परवाज के लिए भारत को अब कठोर कदम उठाने ही होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

भारत की असली ताकत

जब हम भारत के अतीत को देखते हैं, तो जो बात हमारा ध्यान सर्वाधिक आकर्षित करती है, वह है उसकी विलक्षण ऊर्जस्विता; उसके जीवन और जीवन के आनंद की असीम शक्ति; उसकी कल्पनातीत सृजनशीलता। कम से कम तीन हजार वर्षों से- वस्तुतः और भी लंबे समय से -भारत प्रचुरता से और निरंतरता से खुले हाथों व अनंत बहुपक्षीयता के साथ सृजित करता आ रहा है- गणतंत्रों, राज्यों और साम्राज्यों को; दर्शनों, सृष्टि-मीमांसाओं को; विज्ञानों और पंथों को, समुदायों, समाजों और धार्मिक व्यवस्थाओं को, कानूनों व संहिताओं, व्यापारों, उद्योगों को। यह सूची अनंत है और प्रत्येक मद में प्रायः क्रियाशीलता का बाहुल्य है।

वह सृजन करता ही जाता है, करता ही जाता है और न संतुष्ट होता है, न थकता है; वह उसका अंत नहीं करना चाहेगा। आराम करने के लिए स्थान की आवश्यकता भी नहीं लगती, न आलस्य अथवा खाली पड़े रहने के लिए समय की। वह अपनी सीमाओं के बाहर भी विस्तार करता है; उसके जहाज महासागर पार करते हैं और उसकी संपदा का उत्तम अतिरेक छलककर जूडेआ, मिस्र और रोम पहुंचता है; उसके उपनिवेश उसकी कलाओं, उसके महाकाव्यों और उसके पंथों को द्वीप-समूहों में प्रसारित कर देते हैं; उसके चिह्न मैसोपोटामिया की रेतों में पाए जाते हैं; उसके धर्म चीन और जापान को जीत लेते हैं और पश्चिम की दिशा में फलस्तीन और सिकंदरिया तक फैल जाते हैं और उपनिषदों के स्वर तथा बौद्धों की उक्तियां ईसा मसीह के होठों पर पुनः गुंजरित हो उठते हैं। सर्वत्र, जैसी उसकी मिट्टी में, वैसी ही उसके कामों में भरपूर जीवन की ऊर्जा की अति-विपुलता है।...

वस्तुतः इस भरपूर ऊर्जा और भरपूर बौद्धिकता के बिना भारत इतना कुछ कभी नहीं कर पाता, जितना उसने अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के साथ किया। यह समझना भारी भूल है कि आध्यात्मिकता सबसे अधिक वहां पनपती है, जहां की भूमि दरिद्र होती है, जीवन अधमरा होता है और बुद्धि हतोत्साहित तथा भयाक्रांत होती है। ऐसी जो आध्यात्मिकता पनपती है, वह विकृत होती है, क्षयग्रस्त होती है और उससे हमेशा खतरनाक प्रतिक्रियाओं का डर बना रहता है। जब जाति अत्यंत समृद्धता से रह लेती है और भव्यता के साथ विचार कर लेती है, तभी आध्यात्मिकता अपनी ऊंचाइयों और गहराइयों को तथा अपनी निरंतर व बहुमुखी सिद्धि को प्राप्त करती है।...

यदि चाहे, तो भारत उन समस्याओं को निर्णायक मोड़ दे सकता है, जिनके ऊपर सारी मानव जाति परिश्रम कर रही है और लड़खड़ा रही है, क्योंकि उनके हल का सुराग उसके प्राचीन ज्ञान में है।

यदि चाहे, तो भारत उन समस्याओं को एक नया और निर्णायक मोड़ दे सकता है, जिनके ऊपर सारी मानव जाति परिश्रम कर रही है और लड़खड़ा रही है, क्योंकि उनके हल का सुराग उसके प्राचीन ज्ञान में है।

श्री अरविंद

मलाला यूसुफजई | नोबेल विजेता

संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि गाजा में कम से कम 5,479 छात्र, 261 शिक्षक और 95 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मारे जा चुके हैं। बीते सात महीने की जंग ने वहां की शिक्षा को हर स्तर पर तबाह कर दिया है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 09 मई, 1949

हैदराबाद का प्रश्न

हैदराबाद, ८ मई। श्री मंजूर अहमद खां ने, जो पहले नवाब मंजूर जंग के नाम से विख्यात थे, कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर मोहम्मद जफरुल्ला खां द्वारा लेक सक्सेस में हैदराबाद की स्थिति पर उठाये गये प्रश्न का उल्लेख करते हुए कहा कि मोहम्मद जफरुल्ला खां जूनागढ़ और हैदराबाद के सम्बन्ध में उठाये गये अपने मामलों में हार चुके हैं। श्री मंजूर अहमद खां ने आगे बताया कि सर जफरुल्ला ने हैदराबाद के प्रश्न को पुनः उठाने के प्रयास में सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हैदराबाद की स्थिति ''बिगड़'' गई है और उससे ''शांति को खतरा'' है।

श्री मंजूर अहमद खां ने हैदराबाद के प्रश्न को उठाये जाने की आलोचना करते हुए कहा कि मोहम्मद जफरुल्ला खां जूनागढ़ तथा हैदराबाद सम्बन्धी दोनों मामले हार चुके हैं। यदि मुसलमानों की बिगड़ती हुई हालत के सम्बन्ध में उनका वक्तव्य उन हैदराबादी मुसलमानों के बारे में है जो नवस्थापित राज्य से लाभ उठाने के लिए अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान गये तो उस पर मुसलमानों की सहानुभूति होने का कोई कारण नहीं। भारी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनकी मनोवृत्ति दूषित है और जिन्होंने जान-बूझकर भारी गलतियां की हैं। क्या कोई साहसी मुसलमान उनके प्रति सहानुभूति रख सकता है? सर जफरुल्ला हैदराबाद के केवल भूतकालीन हालात को जानते हैं। न्याय के लिए वह इतना कर ही सकते हैं कि वह स्वयं हैदराबाद जाकर वहां के मुसलमानों की वर्तमान हालत देखें और अपना गलत मत बदलें।

हैदराबाद के दूसरे मुस्लिम नेता श्री बाकर अली मिर्जा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा हैदराबाद के प्रश्न को पुनः सुरक्षा परिषद् में उठाने के प्रयास की आलोचना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्रचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री मिर्जा ने कहा कि मोहम्मद जफरुल्ला द्वारा हैदराबाद के प्रश्न को पुनः उठाने से हैदराबाद का भला नहीं हो सकता। मोहम्मद जफरुल्ला ने भूतकाल में सहायता के लिए झूठे वायदे करके, जो कभी पूरे नहीं हुए तथा जिन्हें निभाने का कभी विचार भी नहीं किया गया, हैदराबादियों को भारी हानि पहुंचाई है। हैदराबाद के मुसलमानों को अपनी गलतियों के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ा; वे अब अपने को दूसरों का प्यादा नहीं बना सकते।

आग से निपटने की न तैयारी, न दृष्टि

उत्तराखंड के पहाड़ों पर आग धधकी हुई है। अकेले कुमाऊं क्षेत्र में पांच सौ से भी अधिक जगहों पर दावानल का कहर बरपा है। आसपास के शहरों-गांवों की हवा में इस कदर धुआं घुल चुका है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी जो घट रहा है, उसकी आशंका पहले से ही थी, क्योंकि जंगलों का सुलगना इस साल जनवरी में ही शुरू हो गया था। यह और बात है कि हमेशा की तरह इस बार भी किसी ने समय रहते इसकी सुध नहीं ली। पिछले कुछ बरसों से यह सामान्य सा घटनाक्रम हो चुका है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला पर्यटक सीजन शुरू होता है और जंगल जलना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति के विनाश का दायरा हर वर्ष पिछले साल से अधिक बड़ा होता जाता है। पांच साल पहले ठीक इन्हीं दिनों में कुमाऊं इलाके में चार सौ हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल जले थे। इस साल अभी ही यह क्षेत्रफल दोगुना बताया जा रहा है।

पहाड़ों में इस मौसम में आग लगना आम है। सदियों से यह होता है कि चारे के लिए अच्छी घास उगाने की नीयत से जंगलों में फैली हुई चीड़ की सूखी पत्तियों को नियंत्रित रूप से जलाया जाता था। इस आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग ने बाकायदा पतरौल और अगलैन जैसे पदों पर लोगों की नियुक्ति कर रखी है। समूचा डिपार्टमेंट इस बात को सुनिश्चित करता था कि हर साल अप्रैल-मई-जून में लगने वाली इस आग से कम से कम नुकसान हो। उत्तराखंड बनने के बाद जंगल में लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग से बाकायदा एक विभाग भी बनाया गया। मगर अपने उद्देश्य में वह कितना सफल रहा है, यह सबको दिखाई देता है। हमसे पहले की पीढ़ियां इस आपदा से साल-दर-साल सलीके से लड़ती रहीं। इधर के वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि लंबी-चौड़ी अफसरशाही, नेतागिरी, अखबारबाजी और सोशल मीडिया के बावजूद हालात बिगड़ते चले गए!

दरअसल, हमने एक समुदाय के रूप में सोचना और काम करना बंद कर दिया है। हम एक जिम्मेदार और सभ्य समाज के रूप में रहना भूल चुके हैं। सरकार के पास तमाम संसाधन हैं, लेकिन उसके पास न कोई तैयारी है, न कोई दृष्टि। एक जमाने में आग बुझाने का काम सरकार और जनता, दोनों का साझा होता था। अब दोनों के बीच कैसी दूरी है, बताने की जरूरत नहीं। विकास और वैज्ञानिक प्रगति का आलम यह है कि हमेशा की तरह हर कोई इस बार भी बारिश का ही इंतजार कर रहा है। उसी का सहारा है, हमेशा की तरह!

अशोक पांडे, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

जंगल में आग

हरसंभव प्रयासों से थामा जा रहा दावानल

उत्तराखंड के वन अपनी वनस्पतियों और जैव-विविधता के कारण विश्व धरोहर की हैसियत रखते हैं। इस कारण, इसके संरक्षण के लिए विश्व के तमाम हिस्सों से आर्थिक सहायता भी मिलती रहती है। ऐसे में, यह कहना कि सरकारी नीतियों के कारण वनाग्नि की घटनाएं थम नहीं रही हैं, गलत होगा। आखिर क्यों कोई अपनी उस संपदा को खुद ही नष्ट करेगा, जो उसके लिए कई संभावनाओं के द्वार खोलती हो? अलबत्ता, सरकार ने तो वनों के लिए अलग से मंत्रालय और विभाग बनाए हैं, ताकि इनका उचित संरक्षण हो सके। इन विभागों में अरबों-खरबों रुपये आते हैं, जिनका इस्तेमाल वनों के संरक्षण में किया जाता है। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि वन विभाग भले कभी सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत था, लेकिन आज ये सब बरबादी के कगार पर पहुंच गए हैं, मगर यदि ऐसे आरोपों में दम होता, तो भारत में वन क्षेत्रों के विस्तार या हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। असल में, दिक्कत चंद स्वार्थी लोगों से है। वे सरकारी विभागों में भी पदासीन हैं और समाज की स्थानीय संस्थाओं में भी। वे हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। जब-तब इन पर नकेल जरूर कसी जाती है, लेकिन कानूनी-छिद्रों का फायदा उठाकर ये बच निकलते हैं और फिर से अपनी नापाक मंशा को पूरा करने में जुट जाते हैं। अभी ही दावाग्नि की एक वजह कुछ लोगों द्वारा मौज-मस्ती के लिए जंगलों में आग लगाया जाना है! मजाक-मजाक में किया गया कोई काम कितना भारी पड़ सकता है, यह हम देख ही रहे हैं। अच्छी बात है कि सरकारी तंत्र ऐसे लोगों पर कानूनी दबिश बढ़ा रहा है, जिसका अच्छा नतीजा ही निकलेगा।

सुमन, टिप्पणीकार

स्वार्थी लोगों की करतूत

आजकल उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के अनेक वन क्षेत्र आग की लपटों से धधक रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम देवभूमि में रहने वाले लोग यज्ञ-पुराण का आयोजन करने और देश-देशांतर में आस्था व श्रद्धा के लिए पूजनीय माने जाते हैं, लेकिन कुछ दुष्टात्मा प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हमारे ही बीच में रहते हैं। आगजनी जैसा कुकृत्य करने वालों के बारे में पता होने के बावजूद कुछ लोग इसलिए चुप्पी साध जाते है, क्योंकि यह माना जाता है कि जहां आग लगती है, वहां पर घास की पैदावार अधिक हो जाती है और मवेशियों के चारे के लिए घास की परेशानी नहीं रहती। मगर हमें इन सबसे ऊपर उठना होगा, क्योंकि नुकसान कहीं अधिक है।

विष्णु प्रसाद सेमवाल, टिप्पणीकार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 9 मई 2024

BJP को झटका

जब देश लोकसभा चुनावों में तीसरे चरण के मतदान से गुजर रहा था, तब मंगलवार को अचानक हरियाणा से आई तीन विधायकों के पाला बदलने की खबर ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। खास बात यह कि इन तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश की BJP सरकार अल्पमत में आ गई बताई जा रही है।

फैसले की टाइमिंग | तीनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी का फैसला ऐसे समय किया, जब राज्य में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। राज्य की दसों लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट पड़ने हैं। ऐसे में इन तीन विधायकों का BJP के बजाय कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का एलान स्वाभाविक ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है।

हरियाणा : सरकार पर संकट

राज्य सरकार का भविष्य | ध्यान रहे, इसी साल के आखिर में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में इन विधायकों की समर्थन वापसी के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के सामने अपना बहुमत साबित करने की चुनौती आ खड़ी हुई है। हालांकि दो महीने पहले ही उन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल किया है, इसलिए तत्काल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन अल्पमत सरकार की धारणा को बदलना उनके लिए कठिन होगा।

वैकल्पिक सरकार | विपक्ष की मुश्किल यह है कि कांग्रेस और JJP के विधायक मिलकर भी सदन में बहुमत जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार बनाने की बात करने के बजाय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और तत्काल विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ BJP की ओर से कहा जा रहा है कि JJP विधायकों का एक धड़ा उसके संपर्क में है।

अनदेखी संभव नहीं : ऐसे में अगर ठोस नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो राज्य में तत्काल सरकार गिरने की स्थिति नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा राजनीतिक संकट जरूर खड़ा हो गया है जिसकी अनदेखी करना किसी के लिए भी संभव नहीं रह गया है। प्रदेश और राष्ट्रीय BJP नेतृत्व इस संकट से उबरने की क्या राह निकालता है, कोई राह निकाल पाता है या नहीं, यह स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

चुनावी माहौल पर असर | प्रदेश में कांग्रेस और JJP का मौजूदा रुख बताता है कि दोनों पार्टियां इस स्थिति का अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। ऐन चुनाव के दौरान एक राज्य में दस साल से चलती बीजेपी सरकार का इस तरह अचानक गिरने की स्थिति में आ जाना विपक्ष के लिए मुंहमांगी मुराद मिलने जैसा है। लेकिन वह इसका कितना फायदा सचमुच उठा पाता है और BJP संभावित नुकसान से कितना बच पाती है, इसका पहला ठोस अंदाजा 4 जून को होने वाली मतगणना से ही मिलेगा।

साड्डी दिल्ली

नाम नहीं गुम हुआ

विवेक शुक्ला

आप जब इंद्रप्रस्थ एस्टेट-ITO के रास्ते आगे बढ़ें तो रेड लाइट की दाईं ओर दिल्ली गेट की तरफ जाना होता है जबकि बाईं तरफ जाने पर इंडिया गेट आ जाता है। लेकिन इसी रास्ते पर सीधे जाएं तो बिजी राउज एवेन्यू आपका इस्तकबाल करता है। यह सफर कोई लंबा नहीं है। जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो सड़क की तरफ एक शानदार बिल्डिंग में राउज एवेन्यू कोर्ट का बोर्ड भी नजर आता है। देश की नई राजधानी के निर्माण में जिन ब्रिटिश अफसरों का अहम रोल रहा था, उनमें सर अलेक्जेंडर राउज (1878-1966) खास थे। दिल्ली को देश की नई राजधानी 1911 में बनाया गया और सर राउज 1913 में यहां आए। नई राजधानी के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी (DMC) के चीफ इंजीनियर ह्यू कीलिंग और अलेक्जेंडर राउज की सरपरस्ती में नई राजधानी में पेयजल, सीवरेज, सड़कों, सरकारी दफ्तरों, घरों वगैरह का निर्माण हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बाराखंबा रोड से सटे टॉलस्टॉय रोड का नाम 1970 तक कीलिंग रोड ही था। खैर, राउज 1925 तक कीलिंग के डेप्युटी रहे। फिर 1925 में DMC के चीफ इंजीनियर बने। DMC ही आगे चलकर नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) कहलाई। लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी, 1931 को जब नई दिल्ली का उद्घाटन किया तो राउज यहां के चीफ इंजीनियर थे। उस उद्घाटन समारोह में दिल्ली के चीफ टाउन प्लानर एडविन लुटियंस ने अपने भाषण में राउज के श्रेष्ठ काम का जिक्र किया था। जब नई दिल्ली को खड़ा किया जा रहा था, तब यहां के चीफ टाउन प्लानर एडविन लुटियंस के सबसे भरोसेमंद साथियों में राउज भी थे। उनके नाम पर ही राजधानी की एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम 1940 के आसपास राउज एवेन्यू रखा गया।

Subrata Dhar

बहरहाल, राउज एवेन्यू का 1972 में नाम जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया। तब इस सड़क पर मौजूद एक पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद मूर्ति लगी। लेकिन नया नाम मिलने के बाद भी राउज एवेन्यू का नाम खत्म नहीं हुआ। कह सकते हैं कि इस सड़क के दो नाम हैं- राउज एवेन्यू और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। यह इत्तेफाक ही है कि इसी राउज एवेन्यू पर BJP और उससे जुड़े कई संगठनों के दफ्तर बने। इनमें प्रवासी भवन, मालवीय स्मृति भवन, संस्कृत भारती भवन वगैरह शामिल हैं। इधर ही आम आदमी पार्टी, प्रदेश कांग्रेस और DMK के भी दफ्तर हैं।

एकदा

मौत पर लिखी कविता

एक दिन राजा भोज ने कवि कालिदास से कहा, 'जब मैं यमराज का अतिथि बन जाऊंगा, तब आप मेरी याद में कैसी कविता बनाएंगे। वह श्लोक अभी पढ़ कर सुना दीजिए।' कालिदास दुखी हो गए। उन्होंने राजा की बात नहीं मानी और पत्नी के साथ धारा नगरी छोड़कर शिला नगरी में आ गए। राजा भोज कालिदास के बिना बेचैन थे। कुछ दिन बाद वह योगी के वेश में शिला नगरी जा पहुंचे। वहां भ्रमण करते हुए कालिदास से सामना हो गया। कालिदास ने पूछा, 'हे योगीराज! आप कहां रहते हैं?' योगी ने कहा, 'धारा नगरी।' कवि ने पूछा, 'धारा नगरी में राजा भोज सकुशल तो हैं न?' योगी ने जवाब दिया, 'राजा भोज का अचानक स्वर्गवास हो गया।' सुनते ही कवि धरती पर गिर पड़े और रोते हुए बोले- *अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते*। यानी आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है। सरस्वती बिना आश्रय की हो गई है और सभी पंडित खंडित हो गए हैं। कालिदास दशा देख योगी ने कहा, 'मैं तो मजाक कर रहा था।' तब आंसू पोछते हुए कालिदास बोले- *अद्य धारा सदाधारा, सदालंबी सरस्वती। पंडिताः मंडिताः सर्वे, भोज राजे भुवंगते।* यानी राजा भोज के होने से धारा नगरी और सरस्वती आधारमयी है और सारे विद्वान पंडित सम्मानित हो रहे हैं। अनजाने ही सही पर कालिदास ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी।

Subrata Dhar

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

शी चिनफिंग (Xi Jinping) जिस तरह से PLA का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वह भारत के लिए चेतावनी है

चीनी फौज बदल रही, भारत न रहे पीछे

हर्ष वी. पंत

जब भारत असाधारण रूप से लंबी चुनाव प्रक्रिया में उलझा हुआ है, बाकी दुनिया अपनी प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ रही है। पिछले हफ्ते, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने देश के सशस्त्र बलों के व्यापक पुनर्गठन की ओर कदम बढ़ाते हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की डिविजन स्ट्रैटजिक सपोर्ट फोर्स (SSF) को भंग करने का आश्चर्यजनक फैसला किया। इस डिविजन का गठन उन्होंने 2015 में किया था, जिसका मकसद PLA के स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और साइकॉलजिकल वॉरफेयर से जुड़े हिस्सों का विलय करना था।

सूचना सहायता बल | इसके स्थान पर, शी ने सूचना सहायता बल (ISF) की शुरुआत की जो नेटवर्क सूचना प्रणाली को समन्वित रूप से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस फैसले के बाद अब PLA में चार प्राथमिक शाखाएं हो गई हैं - थल सेना, नौसेना बल, वायु सेना और रॉकेट बल।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान | इस कदम की भूमिका PLA के भीतर चलाए गए उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से तैयार हुई। कई प्रभावशाली जनरल इस अभियान की चपेट में आए। चीनी मिसाइलों के तेजी से बढ़ते भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रॉकेट फोर्स में भी इस वजह से डिसरप्शन आया।

शी की निगरानी को मजबूती | पुनर्गठन का ताजा प्रयास PLA की रणनीतिक क्षमताओं पर शी की प्रत्यक्ष निगरानी को मजबूत करता है और भविष्य में युद्ध के बदलते स्वरूप के मद्देनजर AI और अन्य उभरती टेक्नॉलजी का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर देता है।

आधुनिकीकरण का दशक | पिछले एक दशक में चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया है, जिसका लक्ष्य PLA को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम अजेय ताकत में तब्दील करना है।

PLA में बदलाव

- चीनी सेना में समन्वय और बढ़ेगा
- AI और अन्य टेक्नॉलजी पर जोर
- हो रहे सैन्य क्षमता बढ़ाने के उपाय

अत्याधुनिक हथियार | चीन के सैन्य आधुनिकीकरण का केंद्र बिंदु अत्याधुनिक हथियार और साजो-सामान का विकास व अधिग्रहण रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कमिशनिंग के जरिए नौसैनिक क्षमता में वृद्धि करना, अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों के जरिए वायु सेना का आधुनिकीकरण और उन्नत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के जरिए मिसाइल फोर्स को मजबूती देना शामिल है।

AI Image

भारत के लिए चुनौतियां | कहने की जरूरत नहीं कि चीन का सैन्य आधुनिकीकरण भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां पेश करता है। चीन की बढ़ी हुई सैन्य क्षमताएं इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। देखा जाए तो इस क्षेत्र में चल रहे विवादों पर चीन के रुख में पहले के मुकाबला ज्यादा आक्रामकता अभी से स्पष्ट होने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक ही दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है।

रक्षा पर खर्च | वैसे भी चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का भारत की रक्षा योजनाओं और सुरक्षा चिंताओं पर प्रभाव पड़ता ही है। संभावित चीनी आक्रामकता के खिलाफ एक विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने के लिए भारत अपने सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों में निवेश बढ़ाने को मजबूर है।

मेक इन इंडिया | पिछले दशक में भारत ने अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और इनकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा सुधारों का सिलसिला शुरू किया है। एक महत्वपूर्ण सुधार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भारत के इस पहल का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा क्षमताओं में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

खरीद प्रक्रिया | इसके अलावा, महत्वपूर्ण मिलिटरी हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) और रणनीतिक साझेदारी मॉडल जैसे उपायों का उद्देश्य खरीद प्रक्रियाओं को सहज और सुविधाजनक बनाना और रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

बुनियादी ढांचे का विकास | भारत की सीमाओं पर, विशेषकर चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में, रक्षा बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर बढ़ाया गया है। इसमें सशस्त्र बलों की मोबिलिटी बढ़ाने और उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से सड़कों, हवाई क्षेत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इसके अलावा, भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं - थल सेना, नौसेना और वायु सेना - के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

थिएटर कमांड पर बहस | फिर भी तेजी से सुधार और व्यापक पुनर्गठन की जरूरत बनी हुई है। देश में थिएटर कमांड पर बहस अभी भी अटकी हुई है। मानव संसाधन और टेक्नॉलजी का अनुपात वाजिब स्तर से काफी कम है। चीन के हालिया कदम भारत के लिए एक चेतावनी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को 21वीं सदी के युद्ध लड़ने लायक बनाना जून में आने वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

कभी हिंदी के भी तो थोड़ा करीब आए AI

सचिन बत्रा

हिंदी को 2007 में संयुक्त राष्ट्र की छठी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। विजुअल कैपिटलिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते और लिखते हैं। स्टेटिस्टा के आंकड़े बताते हैं कि हिंदी के इंटरनेट यूजर 50 करोड़ से अधिक हैं। आज पूरी दुनिया अपनी-अपनी भाषा में AI से लेकर डिजिटल औजारों को तराशने, ईजाद करने और भाषागत समस्याओं के वैकल्पिक समाधान खोजने में जुटी है। वहीं, हमारे देश में हिंदी के AI औजारों से लेकर ऑनलाइन परेशानियां पहले जैसी ही बनी हुई हैं।

हिंदी का दायरा | भारत में हिंदी के लगभग 13 हजार समाचारपत्र हैं। बात टीवी की करें तो 100 से अधिक समाचार और मनोरंजन चैनल हैं। इन्हें देखने वाले लगभग 80 करोड़ लोग हैं। रेडियो के भी लगभग 400 चैनल हैं, जिनके श्रोताओं की संख्या करीब 50 करोड़ बताई जाती है। हिंदी के डिजिटल दायरे में चलें तो अकेले फेसबुक पर लगभग 32 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो एक्स (ट्विटर) पर 17 करोड़ लोग हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। यूट्यूब पर 45 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा में विडियो व कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इनमें क्रिएटर्स भी हैं।

AI में हिंदी | फिर भी हम AI की मदद से हिंदी में अनुवाद, विषय-वस्तु निर्माण, पुनर्लेखन, आंकड़ों की छंटाई और भारी-भरकम सामग्री में पैटर्न की पहचान सहित हिंदी में वांछित खोज परिणाम प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए हैं।

समाधान के प्रयास | यूं सरकारी स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रयास जरूर किए गए हैं। जैसे, भारत सरकार ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) के तहत AI से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवाद को बेहतर बनाने का प्रयोग किया था। फिर भी हिंदी भाषा की राह में AI से लैस औजार बहुत कम हैं।

बढ़ता निवेश | इंडियन पब्लिशर डॉट कॉम के मुताबिक, 2022 में भारतीय मीडिया ने AI संचालित समाचार लेखन के उपकरणों के लिए 20 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। वहीं, मीडियानामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 तक भारत में लगभग 50% मीडिया संगठन AI आधारित अनुवाद सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक लगभग 80% मीडिया AI आधारित समाचार प्लैटफॉर्मों को अपना लेगा।

AI Image

कॉमन रूम

प्रयोग भी बढ़ा | आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2023 तक AI की मदद से लिखे गए हिंदी समाचार लेखों की संख्या में करीब 500% की वृद्धि हुई है। आज 30% से अधिक समाचार एजेंसियां AI आधारित न्यूजरूम, तो 50% मीडिया भी अनुवाद के लिए AI का उपयोग कर रहा है। डिजिटल विज्ञापनों को लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने में AI पर निर्भरता लगभग 80% है।

मुश्किलें भी कम नहीं | अनुमान है कि 2025 तक भारत में AI संचालित मीडिया उद्योग लगभग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। IBM की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में हिंदी भाषा के सिर्फ 3% मॉडल उपलब्ध थे, जबकि अंग्रेजी में 60% से अधिक मॉडल विकसित किए जा चुके थे। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक AI आधारित अनुवाद के चलते हिंदी समाचार लेखों में 15% गलतियां पाई गईं।

कायम है उम्मीद | हिंदी भाषा में AI समाधान कम होने के कई ठोस कारण हैं। डेटा की कमी तो है ही, इस वजह से एल्गोरिदम भी प्रशिक्षित नहीं हो पाता। यह तकनीक महंगी है तो हिंदी मीडिया संस्थान इसमें भारी निवेश से हिचकते हैं। मगर AI पर बढ़ती निर्भरता और इसके फायदों के चलते कई मीडिया संस्थान अपने स्तर पर कृत्रिम बौद्धिकता के नए समाधान तलाश रहे हैं। उम्मीद है कि हिंदी भाषा में AI के करिश्माई औजार व इनोवेशन जल्द ही हमारे सामने होंगे।

इस्राइल (Israel) को पसंद ईरान का राजा

शैलेंद्र पांडेय

मिट्टी का, सिलिंडर के आकार का एक टुकड़ा और उस पर अंकित प्राचीन भाषा अक्काडियन के शब्द ईरान के इतिहास की सबसे अनमोल धरोहर हैं। कमाल की बात है कि जिस इस्राइल के साथ ईरान युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया था, उसकी भी इन शब्दों पर पूरी श्रद्धा है। मिट्टी के इस टुकड़े को नाम मिला है साइरस सिलिंडर का और जिसके बारे में इस पर लिखा है, वह शख्सियत है साइरस द ग्रेट, शायद इकलौती वजह जिसके लिए ईरान और इस्राइल एकमत हो जाएं।

AI Image

प्राचीन सुपरपावर | साइरस द ग्रेट या Cyrus II ने लगभग ढाई हजार साल पहले उसी हिस्से पर विशाल साम्राज्य कायम किया, जहां आज ईरान है। कई इतिहासकारों का मानना है कि अपने वक्त में उन्होंने सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत खड़ी की थी और वह पहला साम्राज्य था जिसमें विभिन्न परंपराओं और विश्वास वाले लोगों को समान अधिकार और राजकीय संरक्षण मिला हुआ था।

टाइम मशीन

तीन युद्ध | साइरस द्वितीय का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था, पर्सिस में जो आज के ईरान का Fars प्रांत है। वह अचमेनिद वंश में जन्मे थे। पिता Cambyses I की मौत के बाद साइरस ने गद्दी संभाली। उनकी पहली लड़ाई थी ईसा पूर्व 550 में Median साम्राज्य के खिलाफ। जीत के बाद उन्होंने फारसी जनजातियों को एक किया। उनकी दूसरी विजय थी Lydia साम्राज्य पर। लिडिया में सोने और चांदी के अयस्क इलेक्ट्रम का भंडार था। इस जीत ने ताकतवर साइरस को अमीर भी बना दिया। मेसोपोटामिया के आसपास के इलाकों पर कब्जे के बाद उन्होंने कदम बढ़ाए बेबीलोन की ओर। यही वह अभियान था जिसने साइरस को साइरस द ग्रेट बना दिया। बेबीलोन की जनता अपने राजा नेबोनिदस से त्रस्त आ चुकी थी। 539 ईसा पूर्व में जब साइरस की सेना बेबीलोन पहुंची, तो स्थानीय निवासियों ने खुद ही नगर के द्वार खोल दिए।

मसीहा का दर्जा | Cyrus II ने बेबीलोन के लोगों को अपनी परंपराओं का पालन करने की छूट दी। युद्ध के दौरान देवताओं की जिन मूर्तियों को लूटा गया था, उन्हें वापस करा दिया। राजा नेबोनिदस ने बेबीलोन में यहूदियों को निर्वासन में रखा था। साइरस ने इन्हें आजाद कर दिया। साथ ही, यरुशलम में यहूदियों के तोड़े गए मंदिर को फिर से बनाने में मदद की। इस काम ने साइरस को ऐसा इकलौता गैर-यहूदी बना दिया, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में एक मसीहा के रूप में होता है। Cyrus Cylinder में साइरस द ग्रेट के उन्हीं आदेशों के बारे में लिखा है। कहा जाता है कि यह पहला ह्यूमन राइट चार्टर है।

महान शासक | विद्रोही खानाबदोशों के विरुद्ध अभियान के दौरान 70 बरस की उम्र में साइरस की मौत हुई। उस समय तक वह फारस के सबसे महान शासन बन चुके थे। Cyrus Cylinder को 1879 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने खोजा और तब से यह ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकार में है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान इस्लामिक इतिहास के पहले के पन्ने पलटने से बचता रहा है। हालांकि साइरस द्वितीय का मामला अपवाद है। 1960 के दशक के आखिर में ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने राजशाही की 2500वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन से यह सिलिंडर मंगाकर अपने यहां प्रदर्शित किया था। इस साल के आखिर में साइरस सिलिंडर को इस्राइल भेजा जाना है और ईरान इसका विरोध कर रहा।

लड़कियां फिर आगे

प्रणव प्रियदर्शी

ऐसे समय में जब इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप रोल में महिलाओं की भूमिका लगातार रेखांकित हो रही हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि समाज के अपेक्षाकृत निचले तबकों के लिए शुरू की गई रोजगार योजनाओं में भी उनकी भूमिका बढ़ी हुई पाई जाए। फिर भी यह गौर करने लायक है कि पिछले साल सितंबर में शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग हासिल करने में भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक कुल साढ़े तीन लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकी है। इनमें लड़कियों की संख्या 2 लाख 40 हजार यानी 68.76% है, जबकि लड़कों की संख्या मात्र 1 लाख 10 हजार यानी 31.3%। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि घरों से निकल कर रोजगार हासिल करने या कहें आर्थिक स्वायत्तता हासिल करने की बेचैनी लड़कों के मुकाबले लड़कियों में कहीं ज्यादा है। हालांकि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित आंकड़ों पर थोड़ी बारीकी से नजर डालें तो ऐसे ट्रेंड भी स्पष्ट होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को लेकर समाज में जड़ जमाए स्टीरियो टाइप्स की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि ट्रेनिंग हासिल करने वाली ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं ने सिलाई यानी टेलरिंग के काम को चुना जबकि पुरुषों ने राजमिस्त्री के काम को। कुल 2 लाख 40 हजार महिलाओं में से 2 लाख 30 हजार ने टेलरिंग का काम सीखा, जबकि कुल 1 लाख 10 हजार पुरुषों में से 33,104 ने राजमिस्त्री का काम चुना। साफ है कि महिलाओं के सामने या तो ज्यादा विकल्प थे ही नहीं या उन्हें वे विकल्प चुनने लायक नहीं लगे। बहरहाल, इन सीमाओं के बावजूद यह तथ्य उत्साह बढ़ाने वाला है कि लड़कियां इस योजना के रूप में सामने आए अवसर का फायदा उठाने में आगे रहीं। उनकी यह बेचैनी न सिर्फ उनके अपने करियर और जीवन के लिए अहम है बल्कि भविष्य में ज्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित समाज को आकार देने के लिहाज से भी बेहद उपयोगी साबित होने वाली है।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

झांसे में न आएं

8 मई का लेख 'पिछड़े वोटों की लड़ाई में किसकी होगी जीत' पढ़ा। पिछड़े वर्ग ने दशकों तक एक ही दल को वोट दिया, लेकिन उनके जीवन में बड़ा फर्क पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। पक्के मकान, गैस कनेक्शन, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मदद जैसे लाभों के कारण अब वे घोषणापत्रों से प्रभावित नहीं होते। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करके अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। जीत-हार तो चुनाव नतीजे आने के बाद पता चलेगी, लेकिन मतदाताओं को अपने विवेक से काम लेना चाहिए।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

पहले करनी होगी तैयारी

यह पत्र 7 मई के लेख 'पहाड़ में जंगलों की आग के हैं बड़े खतरे' से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के जंगलों की आग एक बड़ी आपदा है। यह आग कई मामले में पर्यावरण के लिए भी संकट पैदा कर रही है। इसकी वजह से जानवर जंगलों से भागकर बस्तियों में घुस रहे रहे हैं। पानी सूखता जा रहा है। लोगों को रोजमर्रा के हालात से लड़ना पड़ रहा है। हर साल आग लगती है, लेकिन समय रहते बचाव के उपाय नहीं किए जाते। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए।

प्रेरणा मीणा, फरीदाबाद

जानलेवा गर्मी

मई महीने की शुरुआत में ही उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और लू के थपेड़ों से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ गए। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सावधानियां बरतने की जरूरत है। धूप में निकलने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें, सिर ढक कर रखें और खूब पानी पिएं। ORS, लस्सी, छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन भी फायदेमंद रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। इसलिए बढ़ती गर्मी से सतर्क रहते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

चार दिन से हवा खराब, समर एक्शन प्लान का इंतजार – खबर

– इंतजार करते-करते कहीं 'समर' ही न बीत जाए!

सुप्रिया रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

आध्यात्मिक ज्ञान आने के बाद दूर हो जाती हैं चिंताएं

श्री श्री आनन्दमूर्ति

यह संसार पांच भौतिक तत्वों से बना है। इनमें आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्मता के कारण आकाश तत्व का अस्तित्व सिर्फ ध्वनि के माध्यम से सिद्ध होता है। इस आकाश तत्व या इसके ध्वनि तरंगों को समझने के लिए एक विशेष किस्म के वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता होती है। आकाश तत्व को छोड़कर बाकी चार तत्वों को हम अपनी इंद्रियों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। ईश्वर इन पांच तत्वों से भी सूक्ष्म हैं। ईश्वर मानसिक (mind) या अति मानसिक (supermind) दायरे से भी परे हैं। इसलिए अपने मन की सहायता से ईश्वर या भूमा चेतना (universal consciousness) तक पहुंचना असंभव है। इसलिए मन को बार-बार निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि वह मनुष्य की कल्पना शक्ति की पहुंच से परे हैं। यानी साधारण ज्ञान के जरिए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

ईश्वरीय आनंद में प्रतिष्ठित होने पर मन, बुद्धि, शब्द सभी लुप्त हो जाते हैं क्योंकि वह स्वयं आनंद हैं, निरपेक्ष आनंद। स्वयं की चेतना के आनंद की शक्ति के जरिए उनमें प्रतिष्ठित होना पड़ता है। वहां पहुंचने पर मन अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए इन छह बंधनों- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ईश्वर जो हमारे लक्ष्य हैं, वह आंखों के जरिए नहीं देखे जा सकते। अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस सूक्ष्मतर सत्ता को नहीं समझा जा सकता। अणुकण (atom) और अणुओं (molecules) से भी अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियां उन्हें पकड़ पाने में असमर्थ हैं।

पदार्थ के कणों को देखने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। ईश्वर को इन साधनों से नहीं देखा जा सकता। फिर भी ईश्वर साधकों के लिए अदृश्य नहीं हैं। उन्हें देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जिस प्रकार atom और molecules को देखने के लिए बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि की जरूरत होती है, उसी प्रकार ईश्वर को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत होती है।

जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके सभी दुख और चिंताएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि मन ही सुख और दुख का कारण है, पर ईश्वर अतिमानस स्तर (super conscious level) के भी परे हैं। वे पुरातन हैं क्योंकि उनका जन्म काल से परे है। आध्यात्मिकता में स्वयं प्रतिष्ठित होने के कारण वह किसी दूसरे पथ पर निर्भर नहीं हैं। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्मिकता का परमलक्ष्य है, वह है साधना का पथ।

अध्यात्म के पथ पर समर्पित होकर जो व्यक्ति साधना की राह पकड़ता है, वह ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद वह सुख और दुख से परे चला जाता है। निष्कर्ष यह है कि मन और बुद्धि की सीमाओं के कारण हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि तपस्या और साधना से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति क्षणिक और शाश्वत के बीच अंतर समझ पाता है और ईश्वर की प्राप्ति के माध्यम से परम आनंद को प्राप्त करता है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

लोकसभा चुनाव
तीसरा चरण संपन्न

लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की शानदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रसन्नतापूर्वक उल्लेख किया। वास्तव में देश के विशाल आकार तथा मतदाताओं की भारी संख्या को देखते हुए भारत में चुनाव काफी जटिल होते हैं और इनको संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण काम है। 2024 का लोकसभा चुनाव आधे रास्ते में पहुंचने के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य जोश, अनुमानों तथा चुनावी गणित से भरा है। मतदान का तीसरा चरण खासकर भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के लिए इस कारण महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में मतदान हुआ। अपने वोट डालने के लिए दोनों नेताओं की उपस्थिति इस चरण का महत्व बढ़ाती और चुनावी विमर्श बदल देती है। तीसरे चरण में 11 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 283 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ कुल लोकसभा सीटों के 52 प्रतिशत पर मतदान पूरा हो गया है, जबकि अभी चुनाव के तार्किक परिणति तक पहुंचने में एक महीना बाकी है। चार और चरणों के बाद चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। तीसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजनेता चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के अनेक प्रमुख उम्मीदवारों में गुजरात में गांधीनगर से भाजपा के अमित शाह, मध्य प्रदेश में राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में विदिशा से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से सपा की डिम्पल यादव, महाराष्ट्र में बारामती से रांकापा-शरद पवार की सुप्रिया सुले, मध्य प्रदेश में गुना से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कर्नाटक में धारवाड़ से भाजपा के प्रह्लाद जोशी तथा कर्नाटक में शिमोगा से भाजपा के के.एस. ईश्वरप्पा, आदि शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने मतदान के पहले व दूसरे चरण के लिए क्रमश: 66.14 प्रतिशत व 66.71 प्रतिशत मतदान की घोषणा की थी। हालांकि, तीसरे चरण में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मतदान प्रतिशत थोड़ा बेहतर हुआ है। तीसरा चरण पूरा होने के बाद 283 लोकसभा सीटों का भविष्य तय हो गया है। इस प्रकार 52 प्रतिशत सीटों पर मतदान के साथ चुनाव आधे रास्ते तक पहुंच गया है। सभी चरणों में पिछले चुनाव के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कम मतदान निर्वाचन मशीनरी व राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती है जो मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा चरण भाजपा के लिए खासकर महत्वपूर्ण है। 2014 से सत्तारूढ़ पार्टी के समक्ष न केवल अपने मजबूत गढ़ बनाए रखने, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव विस्तार की चुनौती है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता में व्याप्त विभिन्न प्रवृत्तियां और गतिशीलता की गहरी जानकारी सामने आती है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भाजपा की संगठनात्मक शक्ति, जीवन्त प्रचार मशीनरी तथा मोदी का करिश्माई नेतृत्व उसे प्रतियोगिता में अन्य दलों की तुलना में लाभ प्रदान करता है। हालांकि, इसके बावजूद उसके सामने अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विविधताओं की चुनौतियां बनी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान परिणाम भाजपा की नीतियों और नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इससे भारत की भावी राजनीतिक दिशा तय होगी।

जिम्मेदार बनें निर्वाचित प्रतिनिधि

समय आ गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के प्रति जिम्मेदार व ईमानदार बनें। उनको प्रतिबद्ध सामुदायिक नेताओं की भूमिका निभानी चाहिए।

जे.एस. राजपूत
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

भारत में वर्तमान समय चुनाव का है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह राजनीतिक पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता का भी समय है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की है। लेकिन सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है। आमतौर से लोगों को इस बात की ज्यादा चिन्ता नहीं होती है कि चुनावों के विस्तार से खर्च तेजी से बढ़ता है जिसका बोझ उम्मीदवारों के साथ सरकारी खजाने पर भी पड़ता है। चुनाव प्रक्रिया लंबी खिंचने से चुनाव संचालित करने तथा प्रक्रिया पूर्ण करने में श्रमशक्ति और अन्य संसाधनों की बरबादी होती है, जबकि इससे बचा जा सकता है। इसका सबसे बुरा असर स्कूली बच्चों पर पड़ता है क्योंकि चुनाव के हर चरण पर शिक्षक सर्वाधिक आसानी से उपलब्ध श्रमशक्ति साबित होते हैं।

निर्वाचित होने के बाद कोई भी अपनी इच्छा से अगली पीढ़ी के लिए स्थान नहीं छोड़ना चाहता है। चुनाव के समय उन लोगों का व्यवहार भी जनता के समक्ष उजागर होता है जो पहले सत्ता का स्वाद चख चुके होते हैं, पर बाद में जनता उनको सत्ता से हटा देती है। अपनी निराशा के कारण वे ऐसे बयान देते हैं जो पूरी तरह असामाजिक, व्यक्तिगत तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य होते हैं। वरिष्ठ लोगों ने ऐसी स्थितियां पैदा की हैं जहां युवा 'मिलीनियल्स' की खोजी कार्रवाई की जरूरत होती है।

उनको समझना चाहिए कि उनके वरिष्ठ लोगों ने जातीय-गणित का सहारा लेकर, क्षेत्रीय व भाषाई भावनायें भड़का कर तथा सामाजिक विरोधाभास पैदा कर मूल लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को नुकसान पहुंचाया है। इससे सामाजिक सद्भावना कम हो रही है। स्वतंत्र भारत ने अपनी यात्रा की शुरुआत 18 प्रतिशत साक्षरता से की थी जो अब लगभग 80 प्रतिशत हो गई है, जबकि जनसंख्या में 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार हम एक सीखने वाला समाज हैं। हमारा अंतरराष्ट्रीय कद स्वतंत्रता के बाद सर्वोत्तम स्थिति में है। ऐसे में आश्चर्य होता है कि राजनेताओं द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली भाषा इतनी खराब व असभ्य क्यों है। इससे कोई भी पढ़ा-लिखा सभ्य व्यक्ति शर्म का अनुभव करेगा। विद्वान, प्रतिबद्ध तथा अनुभवी का सम्मान हमारी विरासत का लोकप्रिय खजाना है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आज छिन्न-भिन्न हो रहा है।

भारत को कभी भी उस समय के महान विद्वानों की उपस्थिति को अनदेखा नहीं करना चाहिए जिनमें गांधी, पटेल, सुभाष बोस, नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद व अन्य लोग शामिल हैं। भारत को समझने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, टैगोर या श्री अरविंद से अपरिचित कैसे रह सकता है? उम्मीद उन लोगों से है जो कुछ साल पहले स्कूलों में थे और उनको संत-वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम से चमत्कृत होने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं अनेक अवसरों पर देखा है कि भारत के बच्चे उनसे कितना प्रेम करते थे। इसका कारण पोखरण-2 नहीं था, इसका कारण उनके व्यक्तित्व से प्रेम था जिसका हर बच्चा और हर भारतीय अनुसरण करना चाहता था। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसे अनेक विद्वान मिले जो अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। उम्मीद थी कि राजनीति में प्रवेश करने वाले एपीजे व अन्य विद्वानों का अनुसरण कर लोगों के साथ उचित व्यवहार करेंगे।

एपीजे अब्दुल कलाम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले मिलीनियल्स में सर्वाधिक आकर्षण और प्रेम का केन्द्र थे। वे एक पेशेवर नेता थे जो अपने उदाहरण से नेतृत्व करते थे तथा सभी लोगों से हार्दिक रूप से संबंध स्थापित कर लेते थे। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं भक्ति सर्वोच्च स्तर की थी। उन्होंने अनेकानेक लोगों को प्रेरित किया और शान से अपना लक्ष्य प्राप्त किया। वे हर भारतीय पर विजय पाने में सफल हुए, भले ही उसकी जीवन स्थिति, उसका पेशा या उसका वैचारिक झुकाव चाहे जो होता। एपीजे भारत के बच्चों के खासकर प्रिय बन गए क्योंकि वे उनमें उभरते भारत तथा भावी भारत का चित्र देखते थे। उन्होंने लाखों बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता पैदा कर उनको 'विंग्स आफ फायर' प्रदान किए। उन्होंने दो बैग के साथ राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था और पांच साल बाद उन्हीं दो बैग के साथ बाहर निकले। भारत को पंचायत स्तर से संसद तक ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों की आवश्यकता है जिनके साथ हर व्यक्ति जुड़ाव अनुभव कर सके और उनके साथ 'संपर्क' संभव बना सके। आम चुनाव संबंधी जानकारियां हर व्यक्ति तक पहुंचने के साथ दिमाग में ऐसी तथा ऐसी ही अनेक भावनायें पैदा होती हैं।

आम चुनावों में दर्जनों बार वोट देने वाले हम में से हर एक उन मूल परिवर्तनों के बारे में बात करना पसंद करेगा जो नेतृत्व की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर आए हैं। आज सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों के प्रति परस्पर सम्मान और आदर की भावना कम हुई है, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में। हमने विपक्षियों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग देखा है जिसने हम सबको पांच दशक पहले शर्मिन्दा किया होता। लेकिन आज किसी को इसकी चिन्ता नहीं है। लेकिन खुशी का संकेत यह है कि मतदाताओं ने इस पर गौर किया है और वे इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। दूरगामी दृष्टिकोण से देखने पर कहा जा सकता है कि यह प्रवृत्ति कारगर नहीं होगी। दु:ख की बात है कि गांधीजी ने 1922 में जिन चुनावी विकृतियों का उल्लेख किया था, आज वे चुनावों के हर चरण तक पहुंच गई हैं और उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और चीजें चाहे जितनी खराब हो जाएं, उम्मीद तो बनी ही रहती है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों से सामान्य उम्मीदों का उल्लेख करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने हर भारतीय को स्वर दिए थे। उन्होंने कहा था, 'हमें इस बारे में स्पष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने नेताओं से ठीक-ठीक क्या उम्मीद करते हैं। इनमें पंचायत सदस्यों से लेकर नगर निगमों के स्थानीय पार्षद तथा संसद सदस्य तक शामिल हैं।' दूसरे शब्दों में उनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। चाहे पंचायत सदस्य हो, विकस अधिकारी, पार्षद, विधायक, सांसद या मंत्री उनको कम से कम अपनी सर्वोत्तम क्षमता का प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए उनको चुना गया है। हमें समुचित दृष्टिकोण वाली संसद चाहिए जहां लोगों के दिमाग में व्यापक तस्वीर हो और वे छुद्र दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोच सकें।

ऐसी संसद कैसे काम कर सकती है? यह पिछली लोकसभा की तुलना में ज्यादा रचनात्मक भूमिका कैसे निभा सकती है? मुझे यह उम्मीद भी है कि अगली लोकसभा के सम्मानित सदस्य स्पष्ट रूप से व पूरी गंभीरता के साथ देश के समक्ष कोई ऐसे दृश्य नहीं पेश करेंगे जिनसे इस पवित्र सदन का कामकाज प्रभावित होता है और भारत के नौजवानों के समक्ष खराब तस्वीर रखता हो। पिछले दो दशकों में अब तक जो होता था, वह गंभीर चिन्ता का विषय है। वरिष्ठ राजनेता सी. सुब्रमण्यम ने कहा था, 'संसद और विधायिकाओं की कार्यवाहियों में अनुशासनहीनता गंभीर चिन्ता का विषय है। अराजकता से न केवल विधायिकाओं की कार्यवाही में बाधा पड़ती है, बल्कि यह विधायिकाओं के भीतर सदस्यों में हिंसा पैदा करती है। यह सामान्य और लगभग रोज होने वाली घटना बन गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी संसद में कार्यवाही के नियम मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम भला जनता से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह अनुशासन का पालन करेगी तथा कानूनों और नियमों का सम्मान करेगी?' समय आ गया है कि भावी सांसद तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की उम्मीदों के प्रति जिम्मेदारी प्रदर्शित करें, ईमानदार बनें तथा प्रतिबद्ध सामुदायिक नेता बनने का प्रयास करें। उनको भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का प्रयास करना चाहिए। उनको प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए कि संसद में एक मिनट का समय भी बेकार नहीं किया जाएगा। यह नव-निर्वाचित सांसदों की ओर से देश को महान उपहार होगा।

भारत में भिक्षावृत्ति और दान देने की प्रवृत्ति

> कई राज्यों में कानूनी निषेधों के बावजूद भीख मांगना जारी है और भिखारी घरेलू दान के सबसे अधिक प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं।

शैव्या वर्मा
(लेखिका, विवि में शोध प्रबंधक हैं)

भीख मांगना भारत में एक सर्वव्यापी घटना है और यह सामान्य दृष्टि से छिपी हुई है। भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कई परिवार उन्हें दान देते हैं। देश में सार्वजनिक नीति पर चर्चा से भिक्षावृत्ति में लगे लोग बड़े पैमाने पर गायब हैं। अशोक विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी (सीएसआईपी) के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति घरेलू दान के सबसे अधिक प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, जो धार्मिक संगठनों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इससे हमें यह प्रश्न उठता है कि वे कौन सी प्रेरणाएँ हैं जो इतने बड़े अनुपात में परिवारों को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रेरित करती हैं। लिंग, भूगोल और उम्र के आधार पर भिखारियों को सबसे अधिक दान देने वाले कौन हैं? और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान किस रूप में मिलता है? हालांक भीख मांगना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बीस से अधिक रायों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष से 10 वर्ष और उससे भी अधिक की सजा हो सकती है। मौजूदा कानूनों के फायदे और नुकसान एक और बहस का विषय हैं। सीएसआईपी के अध्ययन से पता चला है कि भारतीय परिवारों द्वारा कुल नकद दान में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 23.7 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 27 हजार करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें से भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति पसंदीदा प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। धार्मिक संगठनों, गैर-धार्मिक संगठनों, परिवार और दोस्तों, घरेलू कर्मचारियों, और किसी उद्देश्य का समर्थन करना या याचिका पर हस्ताक्षर करना के बीच घरेलू दान। वे समग्र बाजार आकार और अध्ययन में अन्य प्राप्तकर्ता समूहों के बीच उन्हें दान देने वाले परिवारों के अनुपात के मामले में घरेलू दान के दूसरे सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाजार का आकार और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को औसत नकद भुगतान 2020-21 से 2021-22 तक बढ़ गया है। जबकि भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति पसंदीदा प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, परिवार उन पर अपने पैसे से नहीं बल्कि सामग्री को लेकर भरोसा करते हैं। भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने वाले परिवारों के उच्च अनुपात के बावजूद, उन्हें परिवारों से सबसे कम मूल्य का नकद दान (100 रुपये से कम) प्राप्त हुआ।

जबकि अध्ययन में अन्य प्राप्तकर्ता समूहों की तुलना में भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को नकद दान के लिए सबसे कम प्राथमिकता दी गई थी, इस प्राप्तकर्ता समूह के लिए वस्तु के रूप में दान करने की स्पष्ट प्राथमिकता नोट की गई थी। भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने वालों में से आधे से अधिक ने वस्तु के रूप में दान दिया, जो अन्य प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा प्राप्त वस्तु के रूप में दान से बिल्कुल अलग है। भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देते समय परिवार अधिकतर अपनी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। धार्मिक मान्यताएं शीर्ष प्रेरकों में से एक हैं। इसने 55 प्रतिशत परिवारों का मार्गदर्शन किया जो भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देते थे। धार्मिक मान्यताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दूसरों की मदद करना ईश्वर की सेवा करने का एक तरीका है, और अछे कर्म/सर्वशक्तिमान अछे कर्मों का प्रतिफल देते हैं।

इसके अलावा, पारिवारिक परंपराएं परिवारों को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे गरीबी के कारण दिखाई देने वाली कठिनाइयों से भी प्रभावित होते हैं और वित्तीय संकट में किसी का समर्थन करने के लिए दान करने के लिए प्रेरित होते हैं। सेवा या सेवा प्रदान करना भी भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा के रूप में उभरा। परिवारों को छोटी मात्रा में नकद देना भी आसान लगता है, जिसके कारण कई परिवार भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को कुछ पैसे देने की पेशकश करते हैं। लगभग 60त्न परिवारों ने उन्हें दान देने की प्रतिक्रिया व्यक्त की। अध्ययन में यह भी पाया गया कि भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दिया गया दान 100 रुपये से कम छोटी मात्रा में था। यह जानना दिलचस्प था कि जो दानकर्ता भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं, वे वे लोग हैं जिनकी समाज में असुरक्षित स्थिति है और जो मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों की वृद्ध महिलाएं और परिवार भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के प्राथमिक दाता हैं।

बड़े शहरों के परिवारों की तुलना में ग्रामीण भारत के अधिक परिवार भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देते हैं। वास्तव में, ग्रामीण भारत में भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने वाले परिवारों का अनुपात भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को दान देने वाले परिवारों के अनुपात के राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इसी प्रकार, निम्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणी (एसईसी डी/ई) द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को देना राष्ट्रीय औसत से अधिक था। जबकि उच्च और मध्यम सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों (एसईसी ए, एसईसी बी और एसईसी सी) से लगभग 53त्न परिवारों ने योगदान दिया, 65त्न से अधिक परिवारों ने निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों (एसईसी डी/ई) से भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए योगदान दिया।). लिंग और उम्र के संदर्भ में, 46 से 60 वर्ष की उम्र के बीच की वृद्ध महिलाएं भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी और प्राथमिक दान देने वाली हैं।

भिक्षावृत्ति कई रूपों में सदियों से चली आ रही है। कठिनाइयों का सामना करने के कारण, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति आमतौर पर नकारात्मकता, निराशा, कम आत्मसम्मान और कलंक से पीड़ित होते हैं। भारत में अधिकांशत: भिक्षावृत्ति में लगे लोग अक्सर धार्मिक स्थलों के बाहर दिख जाते हैं।

आप की बात

वोट का महत्व

लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के निर्बाध रूप से संपन्न हो जाने से चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली होगी। मगर दु:ख की बात है कि आयोग तथा विभिन्न दलों द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर मतदान करने की अनेक अपीलों के बावजूद मतदान प्रतिशत मात्र 66 प्रतिशत ही रह गया है। जब एक-एक वोट महत्व रखता है तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मतदान नहीं करना निराशाजनक है। मजेदार बात है कि हर छोटी बड़ी बात के लिए सरकार को कोसने वाले लोग भी वोट देने नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति में कई देशों की तुलना में भारतीय जनता की एकजुटता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उसकी प्रतिबद्धता एक बहुत बड़ा फेक्टर है। मगर वोटिंग के प्रति हमारी गहन उदासीनता हमारे बिखराव को दर्शाती है। अब भी शेष बचे चुनाव के चरणों में मतदाता यदि उत्साह से वोटिंग कर मतदान प्रतिशत बढ़ाएं तो यह राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। हालांकि, अब तक 2019 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान हुआ था, पर इसे शत-प्रतिशत तक ले जाना लक्ष्य होना चाहिए। मतदान के मामले में हिंदी पट्टी हमेशा से फिसड्डी साबित होती रही है और विडंबना है कि यह स्थिति अब भी बनी हुई है।

-सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

पुतिन की धमकी

व्लादीमिर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में पांचवें कार्यकाल के लिए मंगलवार को शपथ ली। इसके एक दिन पहले उन्होंने रूसी सेना, नौसेना और यूक्रेन के निकट तैनात सैनिकों को शामिल कर सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है। रूस द्वारा परमाणु हथियार अभ्यास की यह धमकी पूरी दुनिया और मानवजाति के लिए अभूतपूर्व व असाधारण खतरों से भरी है। रूस के पूर्वज सोवियत संघ ने अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम गिराने से पैदा त्रासदी की प्रतिक्रिया में सारी दुनिया में नाभिकीय निशस्त्रीकरण का अभियान चलाया था। हालांकि, उसने भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए नाभिकीय आयुधों का विकास किया था, पर उनके कभी पहले प्रयोग न करने का वादा भी किया था। सोवियत संघ व अमेरिका के बीच नाभिकीय आयुधों की संख्या घटाने के बारे में साल्ट-1 व साल्ट-2 संधियां भी हुई थीं। लेकिन अब पुतिन ने इस पूरी प्रक्रिया को उलट कर न केवल नए नाभिकीय हथियारों के विकास पर जोर दिया है, बल्कि संभवत: वह सीमित नाभिकीय युद्ध के बारे में भी सोच रहे हैं। पुतिन की इस मानवता-विरोधी सोच पर तत्काल प्रभावी लगाम लगाने की आवश्यकता है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

मवेशियों से क्रूरता

अधिक दूध की मांग पूरी करने के लिए कुछ दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध में पानी मिलाने और नकली दूध बनाकर बेचने जैसे हथकंडे अपना कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता रहा है। निरीह मूक पशुओं के साथ इससे भी अधिक घिनौना कृत्य करते हुए उन्हें आक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन देकर उनका हार्मोन स्तर बढ़ाया जाता है, जिससे वे अधिक मात्रा में दूध देते हैं। लेकिन इस अनुचित व्यवहार से दूध की मात्रा भले ही बढ़ जाती हो, परपशुओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आक्सीटोसिन के प्रयोग से पशुओं की मांसपेशियां ऐंठती हैं और उनको भयानक दर्द होता है। मनुष्यों के लिए भी इस प्रकार अप्राकृतिक रूप से प्राप्त दूध हानिकारक होता है। इससे बच्चों में हार्मोनल परिवर्तन और पशुओं में बांझपन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। वैसे तो आक्सीटोसिन पर समय-समय पर प्रतिबंध की घोषणा हुई, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। पशुओं के साथ हो रही इस क्रूरता पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे मवेशियों से क्रूरता माना है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद देश भर में आक्सीटोसिन के मवेशियों में अनुचित प्रयोग पर लगाम लगेगी।

- रामबाबू सोनी, इंदौर

मायावती का फैसला

बसपा सुप्रीमो मायावती अपने घोषित उत्तराधिकारी एवं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का फैसला किया। इसने मीडिया में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर बहनजी के इस कदम से बहुजन समाज के युवाओं में रोष भी दिखाई दिया है। आकाश आनंद दरअसल बेहद आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे। ऐसी ही एक रैली में विरोधियों को जूते मारने जैसे भाषण पर एफआईआर हो गई थी। लगता है कि सीतापुर की रैली में दिए भाषण ने मायावती को नाराज कर दिया था। लोकसभा चुनाव में मतदान के तीन चरण के बाद ऐसा फैसला निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। इससे बसपा सुप्रीमो के मन में पैदा भय भी प्रकट होता है जो समाज के किसी भी हिस्से को नाराज नहीं करना चाहती हैं। हालांकि, आकाश आनन्द की टिप्पणी भाजपाइयों के प्रति थी और निर्वाचन आयोग ने इस पर अभी कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। लेकिन मायावती अपनी पार्टी का भविष्य संवारने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। देखना होगा कि इसका बसपा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर होगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 71

विनिर्माण में सुधार

इस समाचार में प्रकाशित खबर के अनुरूप ही इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) बनाने के इरादे से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न अंशधारकों से कहा है कि वे विभिन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत की कमी, निर्यात क्षमता,कलपुर्जों तथा सब-असेंबली के मूल उपकरण खरीदारों के साथ-साथ देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही विदेशी और देसी कंपनियों के बारे में जानकारी साझा करें। सरकार का लक्ष्य क्षमता बढ़ाने, किफायत में सुधार करने तथा अगले पांच सालों में 75 अरब डॉलर मूल्य की कलपुर्जा संबंधी पारस्थितिकी तैयार करने का है। हालांकि पुराने उदाहरणों को देखें तो सवाल यही है कि क्या पीएलआई योजना देश के विनिर्माण परिदृश्य को बदलने वाली साबित होगी?

अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच भारत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चीन प्लस एक (चीन से इतर एक अन्य विनिर्माण केंद्र) की रणनीति का हिस्सा बनना चाहता है। इस संबंध में पीएलआई जो कि एक उत्पादन सब्सिडी योजना है, वह विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करना चाहती है। यह सही है कि पीएलआई योजना औद्योगिक नीति के करीब है लेकिन यह भी सही है कि इसकी सफलता सीमित है। देश में मोबाइल फोन निर्माण से जुड़ी पीएलआई को छोड़ दिया जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में महत्त्वपूर्ण विनिर्माण आधार तैयार करने की इच्छुक नहीं नजर आतीं। यह सही है कि आईफोन का निर्माण देश में सफलतापूर्वक किया जा रहा है लेकिन उसके अधिकांश कलपुर्जे अन्य स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि ऐपल के दो वेंडर विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने भारत से कारोबार समेट लिया है।

कुलमिलाकर निवेश भी पीएलआई योजनाओं की शुरुआत वाले अन्य क्षेत्रों के शुरुआती अनुमान से बहुत कम है। इनमें उच्च क्षमता वाले सोलर फोटोवॉल्टिक मॉड्यूल, वाहन और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र शामिल हैं जिनसे बड़े पैमाने पर कामयाबी की उम्मीद है। दुर्भाग्यवश देश की औद्योगिक रणनीति उत्पादक रोजगार तैयार करने और निर्यात क्षमता में इजाफा करने के बजाय आयात प्रतिस्थापन की ओर झुक रही है। पीएलआई योजना कंपनियों का चयन करती है और निवेश और उत्पादन के आधार पर उन्हें 4-6 फीसदी की सब्सिडी देती है। यह कहा जा सकता है कि पीएलआई से जुड़ा निवेश वांछित स्तर पर रोजगार तैयार कर पाने में नाकाम रहा। खासतौर पर कम कौशल वाले रोजगार। टेक्सटाइल के लिए पीएलआई का उदाहरण लिया जा सकता है। टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसमें रोजगार तैयार करने की बहुत अधिक क्षमता है। बहरहाल इस क्षेत्र में निवेश के वृद्धि अनुमान से कम रही। जैसा कि सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने हाल ही में कहा भी, पीएलआई समग्र औद्योगीकरण का उपाय नहीं है। यह निर्यात क्षमता बढ़ा सकता है और कुछ क्षेत्रों में लाभदायक साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र को सब्सिडी देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

आयात प्रतिस्थापन तथा राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा सफलताओं के विचार ने भी टैरिफ संरक्षण में इजाफा किया है। यह उन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होना चाहती हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण अहम है। शुरुआत से ही पीएलआई योजनाओं पर आवंटन की मूल योजना का बहुत छोटा हिस्सा व्यय किया गया है। इसके अलावा सैद्धांतिक स्तर पर भी यह बाजार के कामकाज और अफसरशाही नियंत्रण में इजाफा करने वाला है। ऐसे में नए क्षेत्रों को पीएलआई योजना में शामिल करने के पहले बेहतर होगा अगर सरकार योजना के अब तक के प्रदर्शन का आकलन कर ले। बड़ी कंपनियों को उत्पादन सब्सिडी देना और टैरिफ संरक्षण मुहैया कराना ही लंबी अवधि में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भारत को कहीं अधिक गहरे सुधार की आवश्यकता है। मजबूत और टिकाऊ अधोसंरचना, जिसमें हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है, कम टैरिफ वाली एक मजबूत व्यापार नीति, एक कुशल और नियुक्ति योग्य श्रम शक्ति तथा निवेशकों के अनुकूल कारोबारी माहौल औद्योगिक विकास के लिए अहम है।

बिनय सिन्हा

पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए कठिनाई भरा समय

बाजारों के नेतृत्व और उनकी शैली में बड़ा बदलाव आ रहा है। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा कि 2003 से 2008 के बीच की तेजी के दौर में देखने को मिला था। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

अब जबकि बाजार नई ऊंचाइयों की ओर हैं, तो यह इक्विटी पोर्टफोलियो के संचालन के लिए सही समय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार स्पष्ट रूप से सेक्टर रोटेशन या नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और विगत 15 वर्षों के दौरान अग्रणी रहने वाले इस बार कारगर नहीं नजर आ रहे।

अगर कोविड के समापन के बाद दो वर्षों के मूल्य संबंधी कदमों पर नजर डालें तो बाजार में अलग तरह के विजेता नजर आए हैं। बाजार नेतृत्व में बदलाव की अवधि को देखते हुए कह सकते हैं यह परिवर्तन तेजी के चरण का प्रतीक है और यह तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा।

अर्थव्यवस्था में खपत की हिस्सेदारी में ठहराव है और सकल घरेलू उत्पाद में निवेश की हिस्सेदारी बढ़ी है, ऐसे में अधोसंरचना से जुड़े शेयरों और क्षेत्रों तथा पूंजीगत चक्र को लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के मूल्यांकन में भी भारी इजाफा हुआ है। एक समय अपवाद माने जाने वाले सरकारी उपक्रम अब चलन में हैं। निवशकों को यकीन है कि मोदी सरकार वर्षों से कमजोर प्रदर्शन कर रही और इस कारण सस्ते शेयरों वाली इन कंपनियों की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाएगी। खासतौर पर सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों की तुलना में अपने कमजोर प्रदर्शन में सुधार किया है।

बिजली क्षेत्र के शेयरों के साथ-साथ विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र के शेयरों में भी मजबूती नजर आ रही है। निवेशकों को यकीन है कि आपूर्ति श्रृंखला की विविधता और औद्योगिक नीति के बेहतर इस्तेमाल की मदद से भारत के पास विनिर्माण बाजार की हिस्सेदारी लेने का अच्छा खासा अवसर है। इस क्षेत्र का बाजार काफी बड़ा है और कंपनियां बहुत जल्दी दो से तीन गुना आपूर्ति की स्थिति में आ सकती हैं। बिजली क्षेत्र में बात नवीकरणीय ऊर्जा की हो या ताप बिजली की, भारत को क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। ग्रिड में भी निवेश की जरूरत है। निवेशक यहां मुनाफे की संभावना को महसूस कर सकते हैं क्योंकि यहां बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र में भी निर्यात बढ़ाने और स्वदेशीकरण का अवसर है।

मूल्य संबंधी कदम और क्षेत्रवार नेतृत्व के माध्यम से बाजार स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हम 2003-08 के परिदृश्य की ओर वापस जा रहे हैं। तेजी के उस दौर में बाजार में पूंजी गहन क्षेत्रों मसलन अधोसंरचना और अचल संपत्ति तथा निवेश आधारित क्षेत्रों का जोर था। बाजार राजस्व वृद्धि पर केंद्रित था, न कि पूंजी पर प्रतिफल अथवा नई नकदी के। तथाकथित रूप से दीर्घकालिक क्वालिटी कंपाउंडर (पूरे आर्थिक चक्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र) परिदृश्य ने बाजार को रोक रखा था। वही अंतिम दौर था जब क्वालिटी कंपाउंडर भारत में सस्ते थे। निवेशक किसी भी कीमत पर वृद्धि चाहते थे और पूंजी निवेश की बाजार द्वारा सराहना की जा रही थी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद फंसे हुए कर्ज में इजाफा हुआ और बाजार वृद्धि के कारक दोबारा पिछड़ गए।

वर्ष 2009 के बाद से अभी हाल तक हमने क्वालिटी कंपाउंडर का युग देखा। गुणवत्तापूर्ण शेयर जो आमतौर पर पूंजी पर अधिक प्रतिफल देने वाले, आय के मामले में स्थिर और अनुमान योग्य होते हैं। यह उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों का युग था। इन शेयरों ने 15-20 फीसदी के दायरे में उचित आय मुहैया कराई और उनका विस्तार भी मजबूती से हुआ। इससे उनका प्रदर्शन और बेहतर हुआ। विस्तार का यह दौर अब समाप्त होता नजर आ रहा है और हम ऐसी अवधि के बीच में हैं जहां गुणवत्ता परिदृश्य सामान्य हो रहा है। उनके चर में कमी आने के साथ ही ये शेयर बीते करीब 18 महीनों से सीमित तेजी के दौर में हैं। चूंकि वे बहुत महंगी दरों पर कारोबार कर रहे थे, इसलिए उनके गुणकों के सामान्य होने में वक्त लग सकता है।

इसी प्रकार हमने देखा कि कैसे सरकारी उपक्रमों का मूल्य निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की ओर स्थानांतरित हुआ। यह निजी बैंकों और सरकारी बैंकों के मामले में सबसे अधिक स्पष्ट था लेकिन इसे दूरसंचार, बीमा और विमानन क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। इस स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। सरकारी कंपनियों के शेयर अब कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और 18 से 24 माह की अवधि में उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिफल भी दिया है। इस बात की संभावना नहीं है कि सरकारी उपक्रम अंतहीन समय तक हिस्सेदारी गंवाते रहेंगे। बाजार इस विश्वास में नजर आ रहे हैं कि सरकारी उपक्रम अपनी मौजूदा बाजार हिस्सेदारी को बचाए रखेंगे और उनकी उत्पादकता और मुनाफे में भी सुधार होगा। उनके परिचालन में सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी।

बुनियादी संदेश यह है कि जिस पोर्टफोलियो संरचना ने बीते 15 वर्षों में सफलता दिलाई अब वह कुछ समय से कमजोर है और तब तक कमजोर बना रहेगा जब तक कि गुणवत्ता परिदृश्य के गुणक पूरी तरह बदलते नहीं हैं। अगर आप 2003 से 2008 के बीच बाजार में नहीं थे तो आपने गुणवत्ता संचालित बाजारों के विपरीत नहीं देखा होगा। बाजार का संदेश स्पष्ट है। नेतृत्व बदला है। अब पुरानी व्यवस्था जल्दी नजर नहीं आएगी। इसी प्रकार मिड कैप शेयरों के बेहतरीन प्रदर्शन का रुझान बढ़ती घरेलू आवक की बदौलत हुआ है। इसमें बदलाव आता नहीं दिखता। अगर कुछ वर्ष पहले की बात करें जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इक्विटी प्रवाह के सबसे प्रमुख स्रोत थे, तब मिड कैप शेयर वर्षों तक कमजोर प्रदर्शन करते थे। आज इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

बीते 15 वर्षों के दौरान निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति ने क्वालिटी शेयरों पर पैसे कमाए होंगे और सरकारी शेयरों तथा परिसंपत्ति गहन क्षेत्रों से बचा होगा। तेजी के मौजूदा दौर में यह रणनीति कारगर नहीं दिखती। मिड कैप, सरकारी उपक्रम और निवेश चक्र के लाभार्थी शेयर तेजी की ओर अग्रसर नजर आते हैं। ऐसे में निवेशक को क्या करना चाहिए? निवेश दर्शन को भूलकर जो कारगर हो उस पर टिके रहना चाहिए? गुणवत्ता वाले नामों को त्यागकर विनिर्माण और निवेश शेयरों की खरीद करनी चाहिए? या फिर विपरीत दिशा में जाना चाहिए और पूंजी को पिछड़ रहे और सस्ते हो चुके गुणवत्ता शेयरों में लगाना चाहिए?

इन सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर है कि हम विशुद्ध रूप से प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं या सापेक्ष पर? इसके अलावा यह देखना होगा कि हम लंबी अवधि के जोखिम समायोजन वाले प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं या हमें तिमाही आधार पर मानकों के साथ तालमेल बनाना है? यह निवेशक आधार और उनकी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि वे आपको अल्पकालिक रूप से कमजोर प्रदर्शन करने देने की छूट देते हैं या नहीं।

बाजार की शैली और उसके नेतृत्व में व्यापक बदलाव आ रहा है। ये परिवर्तन हर कुछ वर्ष में होता है और इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। यही वजह है कि किसी एक फंड का हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। कई फंड लंबी अवधि में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं लेकिन शायद ही कोई फंड हो जो हर वर्ष बेहतरीन प्रदर्शन करता हो। इस नेतृत्व परिवर्तन का सामना कैसे किया जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फंड का उद्देश्य क्या है, उसके निवेशकों में कितना धैर्य है और खराब प्रदर्शन के दौरान उनमें कितने समय तक शांति से रहने की क्षमता है। जो भी हो, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के समक्ष कठिन समय है।

(लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)

भारत से क्यों गईं विदेशी वित्तीय कंपनियां?

सन 1992 के प्रतिभूति घोटाले के बाद कई विदेशी बैंकों ने जो अहंकार से भरी चुटकियां लीं और उत्तर दिए उनमें से एक यह भी था, 'अगर आप घर का मुख्य द्वार खुला रखेंगे तो आपके घर में चोरी होने की आशंका है।' यह टिप्पणी सिटी बैंक के एक काउबॉय बैंकर ने की थी। वह विदेशी बैंकों द्वारा एक अपारदर्शी सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकारी बैंकों को धोखा देकर मोटा मुनाफा कमाने को उचित ठहरा रहे थे। भारतीय ऋण बाजार की छोटी सी दुनिया के बाहर उनका ट्रेजरी संचालन एक प्रकार से गुमनाम था लेकिन सिटी बैंक 1990 के दशक के आरंभ में भी एक प्रमुख खुदरा वित्तीय सेवा ब्रांड था जिसने क्रेडिट कार्ड से लेकर उपभोक्ता ऋण तक खुदरा वित्त की गति निर्धारित की। आईसीआईसीआई बैंक उस समय तक एक डेवलपमेंट-फाइनैंस संस्थान था, कोटक महिंद्रा बैंक और ऐक्सिस बैंक तब अस्तित्व में ही नहीं थे और सन 1994 में स्थापित हुए एचडीएफसी बैंक का संचालन भी सिटी बैंक से निकले एक व्यक्ति के हाथों में था।

करीब 30 वर्ष बाद मार्च 2023 में उसी सिटी बैंक ने अपना खुदरा कारोबार ऐक्सिस बैंक को बेच दिया और वह भारत के खुदरा बैंकिंग कारोबार से बाहर निकल गया। यह अपनी तरह का इकलौता मामला नहीं था। वर्षों के दौरान भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी लगभग न के बराबर रह गई है। देश का सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिसकी 42 शहरों में केवल 100 शाखाएं हैं। एचएसबीसी की केवल 26 शाखाएं हैं। 38 अन्य विदेशी बैंकों की मौजूदगी नगण्य है। अकेले एचडीएफसी बैंक की 8,000 से अधिक शाखाएं हैं। सबसे बड़े वैश्विक बैंक मसलन जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, मित्सुबिशी यूएफजे और बीएनपी पारिबा आदि या तो भारत में हैं ही नहीं या फिर उनकी उपस्थिति बहुत मामूली है। भारत के शीर्ष बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, ऐक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। म्युचुअल फंड की कहानी भी ऐसी ही है। शीर्ष 20 म्युचुअल फंड में से बहुत कम में विदेशी संयुक्त साझेदार हैं और उनकी भी भूमिका बहुत सीमित है। अधिकांश फंड पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाले हैं। शीर्ष 10 में इकलौती विदेशी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी निप्पॉन इंडिया है। सबसे बड़े अमेरिकी म्युचुअल फंड भारत में नहीं हैं। मॉर्गन स्टैनली और फिडेलिटी ने भारत से कारोबार समेट लिया और टेंपलटन वृद्धि के लिए संघर्ष कर रही है। बीमा क्षेत्र का मामला थोड़ा अलग है जहां कई विदेशी कंपनियां संयुक्त उपक्रम में साझेदार हैं क्योंकि यह कारोबार थोड़ा अलग प्रकृति का है। परंतु इन पर भी भारतीय प्रबंधन का नियंत्रण है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि भारत सरकार की कंपनी है, वह अभी भी जीवन बीमा कारोबार पर पूरा दबदबा रखती है।

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

यह सब 1990 के दशक के शुरुआती दिनों से एकदम अलग है जब भारतीय नीति निर्माता सतर्क थे और एक तरफ घरेलू हितों और दूसरी ओर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधियों के राजनयिक दबाव के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिकी वित्तीय कंपनियों का भारत में सहज प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया में इस बारे में खूब लिखा गया कि कैसे आकांक्षी भारतीय मध्य वर्ग (उस समय करीब 20 करोड़) जो आर्थिक उदारीकरण से लाभान्वित हो रहा था, उसे खुदरा ऋण, बीमा और म्युचुअल फंड जैसे निवेश उत्पादों की जरूरत पड़ने वाली थी। भारतीयों को इन्हें बेचने के लिए अमेरिकी कंपनियों से बेहतर कौन होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके उत्पाद बेहतरीन हैं और निवेश में उनकी विशेषज्ञता है। विश्व व्यापार संगठन में कई दौर की वार्ताएं इस विषय पर केंद्रित रहीं कि उभरते बाजारों को विकसित देशों की सेवाओं (पढ़ें वॉल स्ट्रीट) के लिए खोला जाए। वाम रुझान वाले राजनेता और अकादमिक जगत के लोगों ने नवउपनिवेशवाद का डर दिखाया। परंतु हुआ एकदम उलटा।

सन 1993-94 में जब छह निजी म्युचुअल फंड को लाइसेंस दिया गया था तब उनमें से कई में विदेशी साझेदार थे। बाद में और विदेशी म्युचुअल फंड भारत में आए लेकिन उनमें से शायद ही कोई अपने मूल स्वरूप में नजर आया। पायनियर, ब्लैकरॉक, अलायंस कैपिटल, सन एफऐंडसी, मॉर्गन स्टैनली, जार्डाइन फ्लेमिंग, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स आदि ऐसे फंड हैं जो यहां से चले गए। इसके विपरीत भारतीय फंड कुछ ऐसे विदेशी साझेदारों के साथ बने रहे जो सक्रिय नहीं हैं। जेएम फाइनैंशियल, डीएसपी, आदित्य बिड़ला, श्रीराम आदि इसके उदाहरण हैं।

लाखों भारतीय इस रुझान को भारतीय उद्यमियों की महानता के प्रमाण के रूप में देखेंगे। यह सही है कि भारतीय उद्यमियों और प्रबंधकों ने बहुत अधिक प्रतिभा और क्रियान्वयन कौशल दिखाया है लेकिन विदेशी वित्तीय कंपनियों की भारत छोड़ने की नीति की वजह अलग है। साफ कहें तो सन 1990 के दशक के मध्य में भारतीय मध्य वर्ग को लेकर जो भी अनुमान लगाए गए थे वे गलत साबित हुए। मध्य वर्ग की समृद्धि इस गति से नहीं बढ़ी कि विदेशी कारोबार उसका लाभ ले सकें। ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से हुआ। उत्पादकता कमजोर बनी रही, भ्रष्टाचार और कर दरें ऊंची बनी रहीं और सांठगांठ वाले पूंजीवाद ने 2000 के दशक के मध्य में बुनियादी वृद्धि को नुकसान पहुंचाया। परिणामस्वरूप सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

2005 से 2008 के बीच समृद्धि में सुधार विशुद्ध रूप से तमाम भूभागों में वैश्विक तेजी की बदौलत हुआ। इससे कई परिसंपत्तियों की कीमतें बढ़ीं और वित्तीय सेवाओं में अल्पकालिक तेजी आई। परंतु वैश्विक वित्तीय संकट ने 2008 में भारत पर भी असर डाला और हम एक बार फिर दशक भर के संघर्ष में उलझ गए। विदेशी कंपनियां वैश्विक वित्तीय संकट से बुरी तरह कमजोर पड़ चुकी थीं और उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। भारतीय कंपनियों के पास ऐसा विकल्प नहीं था। उन्होंने समय बिताया और धीरे-धीरे बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसलिए जब ग्राहकों को डिजिटल बनाने जैसे उथलपुथल मचाने वाले अवसर आए तो घरेलू बैंकों की तैयारी बेहतर थी। इसी प्रकार जब कोविड के बाद शेयर बाजार ने गति पकड़ी तो घरेलू म्युचुअल फंड और ब्रोकरेज फर्म तेजी से विकसित हुए। वित्तीय क्षेत्र में भारतीय कंपनियां स्पष्ट विजेता बनकर उभरीं जबकि विदेशी कंपनियां पिछड़ गईं। ध्यान रहे अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए विदेशी कंपनियों के व्यक्तिगत उत्पाद बने रहे। उनकी मजबूत उपस्थिति बरकरार है।

(लेखक मनीलाइफडॉटइन के संपादक और मनीलाइफ फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं)

आपका पक्ष

कैसे रुके चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल

चुनावों के मद्देनजर अवैध धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी बैंकों को निर्देश देना चाहिए कि वे एक लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर नजर रखें। साथ ही बैंकों को संदिग्ध लेनदेन पर निगाह रखने और इसकी जानकारी स्थानीय चुनाव अधिकारी या पुलिस को देने के आदेश भी होने चाहिए। ई-कॉमर्स के जरिये होने वाले लेनदेनों पर पुलिस के साइबर सेल को कड़ी नजर रखना होगी। साथ ही सीमावर्ती जिलों के अफसरों का एक व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनाया जाए जिसमें वे एक-दूसरे से जानकारियां साझा करें। सभी चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच की जाए, खास तौर पर रेत के खाली ट्रकों और डंपरों की जांच की जाए क्योंकि इनका उपयोग गैरकानूनी रूप से शराब और नकदी लाने-ले जाने के लिए हो सकता है। एटीएम का कैश

पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बुधवार को चुनावी ड्यूटी पर लगे एक पुलिसकर्मी ने डाक मतपत्र द्वारा मतदान किया

परिवहन करने वाले वाहनों की भी जांच जरूरी है। राज्यों ही नहीं बल्कि जिलों की सीमाओं पर बने नाकों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए कि अगर कोई वाहन नाके पर बिना रुके दूसरे राज्य या जिले में प्रवेश करे तो वहां तक सूचना पहुंच जाए और उस वाहन को आगे रोककर विधिवत चेकिंग की जा सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

दुनिया भर में रेड क्रॉस का महत्त्व

दुनिया भर में हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम है, 'मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है।' इस थीम से ही साबित हो रहा है कि यह संस्था निःस्वार्थ भाव से काम कर रही है और दूसरों की मदद करके जो खुशी हासिल होती है वही सच्चा इनाम होता है। इतिहासकार बताते हैं कि यह दिवस हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1859 में सोल्फेरिनो युद्ध में हजारों सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और हजारों घायल हुए थे। इन घायल सैनिकों की हालत देखकर हेनरी ड्यूनेंट का हृदय विचलित हुआ तो उन्होंने आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा कर इन सैनिकों की मदद की थी। हेनरी ने इसका जिक्र अपनी किताब 'ए मैमरी ऑफ सोल्फेरिनो' में भी किया है। रेड क्रॉस डे वैसे तो पहली बार वर्ष 1948 में मनाया गया था लेकिन इसे आधिकारिक मंजूरी वर्ष 1984 में मिली थी। रेड क्रॉस के नाम पर आज भी मानवता के कई काम बिना भेदभाव के हो रहे हैं। दुनिया के देशों में जब भी कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य तो यह संगठन पीड़ित लोगों के लिए मददगार बनता है। हमारे देश में भी यह हर आपदा में अपनी भूमिका निभाता है। भारत में रेड क्रॉस की 700 से ज्यादा शाखाएं हैं। देश में यह संगठन रक्तदान शिविर लगाकर लोगों की सेवा में जुटा रहता है। वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। समाजसेवी लोग इससे जुड़कर मानवता की सेवा कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी इसने अहम भूमिका निभाई थी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के जंगल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पेड़ से झड़ी सूखी पत्तियां एकत्र कर हटाया। राज्य के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है जिसे और फैलने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दैनिक जागरण

सुधार की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए

बेतुके बयानों का सिलसिला

कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स की पैरवी करने वाले बयान से उबरी भी नहीं थी कि उन्होंने भारत की विविधता का बेतुके तरीके से चित्रण करते हुए यह कह दिया कि दक्षिण के लोग अफ्रीकियों, पूर्वोत्तर के चीनियों, पश्चिम के अरबों और उत्तर भारत के श्वेतों जैसे दिखते हैं। इसके पहले शायद ही किसी ने विभिन्न रूप-रंग वाले भारतीयों को ऐसी उपमा दी हो। यह उपमा बेतुकी ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। इसमें नस्ली सोच भी झलकती है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुछ नासमझ लोग पूर्वोत्तर भारत के लोगों को चीनी कहकर चिढ़ाते हैं या काले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। चुनाव के मौके पर कोई भी विरोधी दल ऐसा ही करेगा। कांग्रेस को एक बार फिर सैम पित्रोदा के कथन से वैसे ही पल्ला झाड़ना पड़ा, जैसे विरासत टैक्स वाले बयान से झाड़ना पड़ा था। इससे बात बनी नहीं और इसी कारण सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा, जिसे पार्टी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि वह कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए थे। इसलिए और भी, क्योंकि वह यह भी कह गए थे कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर भारत के विचार के विपरीत है।

निःसंदेह बात केवल सैम पित्रोदा की ही नहीं है। बीते दिनों कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने पार्टी की फजीहत कराने वाले बयान दिए हैं। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान बलिदान पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में यह बयान दिया कि वह पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब नहीं, बल्कि आरएसएस के करीबी पुलिस अफसर की गोली का निशाना बने थे। विरोध और फजीहत होने पर वह तो लीपापोती में लग गए, लेकिन शशि थरूर बीच में कूद पड़े और उन्होंने यह मांग कर दी कि विजय वडेट्टीवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। आखिर वह यह कैसे भूल गए कि इस मामले की जांच भी हुई थी और अजमल कसाब को फांसी भी हुई थी? उस समय मनमोहन सरकार सत्ता में थी और खुद शशि थरूर इस सरकार में मंत्री थे। आखिर शशि थरूर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिसके जो मन में आ रहा है, बिना सोचे-समझे बोल रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दिनों पुंछ में आतंकी हमले को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कह दिया कि यह हमला भाजपा की चुनावी नौटंकी है। बाद में उन्हें भी अपने इस बयान के लिए सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस यह समझे तो बेहतर कि उसके नेताओं के बेतुके बयान उस पर बहुत भारी पड़ रहे हैं।

रफ्तार का कहर

अच्छी सड़क पर अनियंत्रित रफ्तार से वाहन चलाने की प्रवृत्ति जानलेवा है। यह बात कई बार साबित हो चुकी है। फिर भी वाहन चलाने वाले नहीं मानते। हाथ में स्टेयरिंग आते ही सड़क को मैदान समझ लेते हैं और गाड़ी से खेलने लगते हैं। एक बार फिर झारखंड में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। धनबाद और गिरिडीह में सोमवार को आठ लेन सड़क पर बेहद तेज गति से चल रही स्कार्पियो ने स्कूटी से जा रहीं दो बहनों की जान ले ली। स्कार्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक लेन के डिवाइडर से टकरा कर वह उछल गई और दूसरी लेन में आ गई। इसके बाद स्कूटी सवारों को रौंद दिया। यह भी पता चला कि स्कार्पियो सवार रील बना रहा था। इसी क्रम में चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया। मंगलवार को गिरिडीह से आइआरबी जवानों को लेकर गढ़वा जा रही तेज रफ्तार बस बगोदर में जीटी रोड पर डिवाइडर से टकरा गई। एक जवान की मौत हुई और 39 घायल हो गए। यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि अच्छी सड़क लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है या बनाई जाती है, न कि किसी की जान लेने के लिए। अच्छी सड़क इसलिए बनाई जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय की बचत हो। उबड़-खाबड़ और टूटी सड़क पर चलने में जो परेशानी होती है, उससे राहत मिले। खराब मार्ग वाहनों के ईंधन और रखरखाव पर अनावश्यक खर्च का कारण बनते हैं, उससे निजात मिले। देश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या भयावह है। झारखंड भी अछूता नहीं है। वाहन चलाने वालों में नाबालिगों की अच्छी-खासी संख्या है। दुर्घटनाओं को रोकना है तो सड़क सुरक्षा और लोगों की जान को प्राथमिकता देनी ही होगी।

> हाथ में स्टेयरिंग आते ही कुछ लोग रोड को मैदान समझ लेते हैं और गाड़ी से खेलने लगते हैं। इसकी फिर धनबाद एवं गिरिडीह में पुनरावृत्ति हुई

बेनकाब होते पश्चिम के दोहरे मानदंड

बलबीर पुंज

जो पश्चिमी देश जिन उपायों को अलोकतांत्रिक बताकर दूसरों को उपदेश देते रहे, वही आज उनका आसरा ले रहे हैं

अवधेश राजपूत

अमेरिका और यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में फलस्तीन के साथ-साथ आतंकी संगठन हमास के समर्थन में प्रारंभ हुआ आंदोलन यहूदियों-इजरायल के प्रति घृणा में बदल गया है। इसमें 'हम हमास हैं' और 'हमास जिंदाबाद' जैसे नारों के साथ इजरायल पर फिर से नृशंस जिहादी हमलों को दोहराने की कामना की जा रही है। इससे याद आ रहा है कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों में क्या हुआ था? तब सीएए के विरुद्ध कई प्रदर्शनकारियों ने मजहबी नारा बुलंद किया था। उसी दौरान राजधानी दिल्ली में भीषण दंगा भड़का था। इसी तरह जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के एक वर्ग ने आंदोलन किया, तब एक वीडियो में खालिस्तान समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का हश्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह करने की धमकियां दी गई थीं।

जिस तरह भारत में किसान आंदोलन और सीएए-विरोधी प्रदर्शनों को विपक्षी दलों के प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन से राष्ट्रविरोधी शक्तियों ने 'हड़प' लिया था, उसी तरह अमेरिका में भी कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के शामिल होने की पुष्टि की है। जिन व्यक्तियों-समूहों पर भारत में सीएए-विरोधी प्रदर्शनों और किसान आंदोलन के वित्तपोषण का आरोप लगा था, लगभग उन्हीं लोगों की भूमिका अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इजरायल-यहूदियों के खिलाफ छात्रों को भड़काने में सामने आ रही है। इसमें सबसे प्रमुख नाम अमेरिकी धनाढ्य जार्ज सोरोस का है, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी अपनी घृणा खुलकर व्यक्त कर चुका है। प्रदर्शनकारी छात्रों को जिस 'स्टूडेंट फार जस्टिस इन फलस्तीन' का समर्थन मिल रहा है, वह सोरोस की कई संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित है। यहूदी विरोधी आंदोलन को उन कट्टरपंथी छात्रों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिन्हें सोरोस द्वारा धनपोषित 'यूएस कैंपेन फार फलस्तीनी राइट्स' से पैसा मिलता है। यह समूह फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के एवज में छात्रों को अच्छे-खासे पैसे दे रहा है।

भारत में भी सरकार-विरोधी आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों के लजीज भोजन और आरामदायक अस्थायी आवास में ठहरने की तस्वीरें सामने आई थीं। ठीक उसी तरह अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए लजीज भोजन के साथ प्रदर्शनस्थल पर कई दिनों तक जमे रहने के लिए एक जैसे टेंटों की व्यवस्था की गई है, जिनकी एक ही स्रोत से आनलाइन खरीद हुई है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों की अराजकता और उनकी बेतुकी मांगों से आजिज आ चुकी पुलिस इन टेंटों पर बुलडोजर चला रही है। भारत में ऐसा कुछ किया गया होता तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश आसमान सिर पर उठा लेते।

भारत में 'शाहीन बाग' और 'सिंघु बार्डर' पर महीनों ऐसे अराजक प्रदर्शन चले, जैसे अमेरिका मे कुछ दिनों से चल रहे हैं और जिनसे वह सख्ती से निपट रहा है। अमेरिका में छात्र आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में वहां की संसद द्वारा पारित यहूदी-विरोधी कानूनी परिभाषा के विस्तार हेतु विधेयक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विधेयक के कानून बनते ही वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन या भविष्य में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने वाले और इजरायल को निशाना बनाने वाले संस्थानों के वित्तपोषण और अन्य संसाधनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। कल्पना कीजिए कि यदि भारत में ऐसा कोई हिंदू समर्थित कानून मोदी सरकार संसद में पारित कर दे तो अमेरिका और यूरोपीय देश हमें सहिष्णुता-समरसता आदि विषयों पर उपदेश देने लगेंगे। जो अमेरिकी शिक्षण संस्थान इस समय यहूदी-विरोधी अभियानों का केंद्र बने हुए हैं, उन्हीं से एक रटगर्स विश्वविद्यालय 2021 के 'डिस्मेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व' सम्मेलन का हिस्सा बन चुका है। इसके उलट भारत में शाहीन बाग से लेकर कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर अराजकता के मामले में मोदी सरकार ने धैर्य का परिचय दिया। तब अमेरिका, कनाडा के अलावा कई यूरोपीय देश भारत को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'मानवाधिकार' पर उपदेश दे रहे थे। जबकि कनाडा में ट्रक चालकों के प्रदर्शन की स्थिति में वहां आपातकाल लगा दिया गया था। आज अमेरिका में प्रदर्शनकारी छात्रों को निर्ममता से खदेड़ा जा रहा है।

वर्ष 1991 तक विश्व द्वि-ध्रुवीय था। वामपंथ नीत सोवियत संघ के विघटन के बाद माना जाने लगा कि विश्व में अमेरिका के नेतृत्व वाले केवल एक ही ध्रुव का प्रभुत्व रहेगा। हालांकि आज दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। इसमें सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं। इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली 'राज्यहीन', परंतु बिना उत्तरदायित्व वाला समूह है। किसी उपयुक्त संज्ञा के अभाव में इस वर्ग को 'वोक' कहते हैं। यह समूह छोटा, अति-मुखर और आक्रामक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकारों को उनके एजेंडे को लागू करने से रोकने एवं व्यवस्था को पंगु करने का प्रयास करता है। वाम-फासिस्ट वैचारिक-अधिष्ठान से प्रेरित यह गिरोह, बिना किसी अपराधबोध के जनादेश के हरण में पारंगत है। इससे जुड़े लोग मानते हैं कि शेष समाज निर्णय लेने में असमर्थ है, लिहाजा उन्हें ही उसका भला करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। यह गिरोह 'शांतिपूर्ण-विरोध' की आड़ में लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन, हिंसक आचरण, जनजीवन में व्यवधान और शासन-प्रशासन को डराने-धमकाने की नीति अपनाता है। जब सत्ता-अधिष्ठान बलप्रयोग पर विवश होता है, तब यही कुनबा स्वयं को पीड़ित बताने के लिए मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है।

जिस 'टूलकिट' का भारत में सीएए और कृषि-सुधार विरोधी प्रदर्शनों में उपयोग हुआ था, अब जब अमेरिका उसका शिकार बना है तो उसकी आंखें खुल रही हैं। अराजकता को समाप्त करने हेतु जिन उपायों को अक्सर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश दमनकारी और अलोकतांत्रिक बताते हुए निंदा करते हैं, वे उनका कहीं अधिक भयंकर रूप में अपने यहां उपयोग कर रहे हैं। क्या यह स्वयंभू लोकतांत्रिक देशों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाने की पराकाष्ठा नहीं?

(स्तंभकार 'ट्रिस्ट विद अयोध्याः डिकोलोनाइजेशन आफ इंडिया' पुस्तक के लेखक हैं)

response@jagran.com

मतदान को मजहब से जोड़ने की कोशिश

अवधेश कुमार

मतदान को दीन-ईमान और वोट जिहाद से जोड़ना देश की आंतरिक शांति के लिए शुभ संकेत नहीं

वर्तमान लोकसभा चुनाव इस मायने में भी चिंता पैदा कर रहा है कि इसमें एक समुदाय के दीन और ईमान को मतदान से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी चुनाव में हमने 'वोट जिहाद' जैसे शब्द सुने और यह भी कि हमारा ईमान अमुक दल यानी भाजपा को वोट देने की इजाजत नहीं देता। लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं, किंतु वोट भी जिहाद की परिधि में आ सकता है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। वोट जिहाद शब्द का सार्वजनिक प्रयोग कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने सपा के प्रत्याशी के समर्थन में फर्रूखाबाद की एक जनसभा में किया। उन्होंने कहा, 'बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होकर, खामोशी के साथ, एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं।' उस मंच पर अनेक मुस्लिम नेता बैठे थे, जिनमें सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। मारिया ने कहा कि मैंने सुना कि कुछ मुस्लिमों ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के साथ मीटिंग की। उनका समाज से हुक्का-पानी बंद कर देना चाहिए। यह बताता है कि वर्तमान राजनीति, भाजपा और चुनाव को लेकर मुसलमानों में किस तरह का सोच पैदा करने की कोशिश हो रही है।

झूठ फैलाकर एक समुदाय के अंदर मजहबी गुस्सा पैदा करने का अभियान चल रहा है। मारिया ने चुनावी मंच से भाषण नहीं दिया होता तो यह वीडियो के रूप में उपलब्ध नहीं होता। अंतर्धारा में चलता रहता। कई जगहों पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह चुनाव नहीं, तुम्हारे लिए इस्लाम को बचाने का प्रश्न है। एक वीडियो में मौलाना कह रहे हैं कि वोट को दीन से अलग मत मानना। एक अन्य वीडियो में कहा जा रहा है कि आपको फलां-फलां से बचना है तो भाजपा के विरुद्ध वोट करो। ऐसे-ऐसे विचार प्रकट किए जा रहे हैं मानों चुनाव कोई धार्मिक-मजहबी गतिविधि है। यह ऐसी खतरनाक कोशिश है जिस पर रोक नहीं लगी तो आगे देश के लिए अनेक समस्याएं पैदा होंगी। पता नहीं आगे किस-किस सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया, कानून या प्रशासनिक विषय को दीन का प्रश्न बना दिया जाए।

चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस सहित आइएनडीआइए के कई घटक दल अपने वक्तव्यों से ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों का एक भी वोट उनके खाते से बाहर न जाए और भाजपा को किसी कीमत पर न मिले। इसके लिए हर तरह के दांव आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द प्रयोग नहीं किया है। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अध्याय दिया। इसमें अत्यंत चतुराई से उसने सार्वजनिक नौकरियों से लेकर खेल और कला जगत में उनको प्रतिनिधित्व देने, आर्थिक-सामाजिक विकास करने, समाज की मुख्यधारा में लाने, उनकी सहमति से पर्सनल ला में सुधार को प्रोत्साहित करने आदि की बातें लिखी हैं। पर्सनल ला का अर्थ ही शरीयत कानून होता है। इस प्रकार मुस्लिम वोट के लिए विपक्षी दल मुसलमानों को आम समाज से अलग बांटने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के वक्तव्यों और अतिवादी आरोपों के कारण मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे तत्वों को मतदान तक को जिहाद, ईमान और दीन का विषय बनाने का प्रोत्साहन मिला है। पूरे देश में अनेक मुस्लिम संस्थाएं और कथित एक्टिविस्ट मुसलमान घूम-घूमकर अपने समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं कि वे कांग्रेस या उनके साथी दलों के पक्ष में ही वोट करें एवं हर हाल में भाजपा को हराएं। यह अभियान इतने व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसकी शायद जमीन पर काम न करने वाले को कल्पना नहीं होगी। इन सबकी कोशिशों से पूरा माहौल ऐसा बन गया है, मानों यह चुनाव मुसलमानों एवं भाजपा के बीच है। जबकि यह सच नहीं है। मुसलमानों के आर्थिक विकास, सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी, सरकारों के कल्याण कार्यक्रमों के आंकड़े आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्हें कहीं ज्यादा लाभ पहुंचा है। सरकारी नौकरियों में पिछले नौ वर्षों में मुसलमान कर्मचारियों की संख्या दोगुनी हुई है। सिविल सेवाओं में रिकार्ड संख्या में मुसलमान आ रहे हैं।

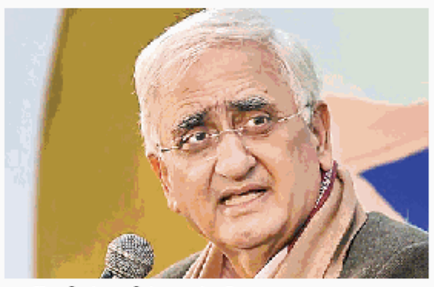

खुर्शीद की मौजूदगी में उठा वोट जिहाद का मुद्दा। फाइल

भाजपा सरकारों के कल्याण कार्यक्रमों एवं सामाजिक विकास संबंधी योजनाओं का लाभ जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को ज्यादा मिला है। मजहब के आधार पर सरकारी भेदभाव का एक भी पुष्ट प्रमाण नहीं है। एक साथ तीन तलाक इस्लाम का भाग नहीं है। अनेक इस्लामी देशों ने इसे समाप्त कर दिया, फिर भी भारत में इसके विरुद्ध कानून को इस्लाम विरोधी करार दिया गया। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने का विषय है, जिसका मुसलमान और इस्लाम से लेना-देना नहीं। समान नागरिक संहिता, गोरक्षा या अन्य विधान किसी कोने से इस्लाम या मुसलमान विरोधी नहीं हैं, किंतु मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सहित अन्य दलों ने ऐसा माहौल बनाया है, जिसमें इस तरह के स्वाभाविक प्रगतिशील विधान भी मजहब विरोधी साबित किए जाने लगे हैं। यह खतरनाक स्थिति है। किसी समुदाय के अंदर इस तरह का भाव पैदा करना देश की आंतरिक शांति के लिए शुभ संकेत नहीं। ऐसे विचारों का परास्त होना देश और आमजन के हित में है। किसी व्यक्ति या समुदाय का अधिकार है कि वह जिसे चाहे वोट दे, जिसका चाहे विरोध करे, किंतु इस तरह चुनाव को मजहब का विषय बनाना अस्वीकार्य है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

गुरु की महिमा

गुरु शब्द में 'गु' का अर्थ है अंधकार और 'रु' का अर्थ है मिटाने वाला। यानी अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार जो शिष्य के आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है उसे गुरु कहते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है। गुरु उस शिष्य में नए मनुष्य को जन्म देता है, इसलिए वह ब्रह्मा है।

गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है कि कहीं शिष्य साधना से विचलित न हो जाए। गुरु विष्णु की तरह है। शिष्य के दोषों का संहार करने के कारण गुरु को महेश कहा गया है। व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह के दलदल में फंसकर बुरे कर्म करने लगता है तब संसार की नजर में वह घृणा या उपहास का पात्र बनकर हीनभावना से भर जाता है। जब व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है, तब उसे उबारने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु रूप में प्रकट होता है।

गुरु के सान्निध्य के लिए शिष्य में समर्पण की आवश्यकता होती है। अन्यथा गुरु पास होते हुए भी उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु के साथ कभी छल न करना, उसकी अवहेलना न करना शिष्य के परम कर्तव्य हैं। आवश्यक है कि हम अपने गुरु की महिमा का केवल बखान ही न करें, बल्कि उसके बताए मार्ग पर चलकर उसकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बनें। गुरु से कभी झूठ न बोलें, गुरु के साथ कभी छल न करें। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण ही सच्ची भक्ति है। ऐसा कर हम पाप के दंड से बच सकते हैं।

अवधविहारी शुक्ल

बेटियों की सुरक्षा का सवाल

सुनीता मिश्रा

> सच तो यह है कि हम आज भी बच्चियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक समाज नहीं बना पाए हैं

हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित निजी स्कूल के छात्रावास में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप छात्रावास की संचालक और स्टाफ पर लगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी जांच एसआइटी से कराने के निर्देश दिए हैं। एक स्त्री के बिना सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेदों-पुराणों में भी नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय और उच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में नारी को लक्ष्मी, बच्चियों को देवी जैसे कई सम्मान सूचक नामों से अभिहित किया जाता है। हर साल नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है, लेकिन सच तो यह है कि कि हम आज भी बच्चियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक समाज नहीं बना पाए हैं। आज के जमाने में बच्चियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि देश को शर्मसार करने वाली ज्यादातर ये घटनाएं घर, शिक्षा के मंदिर, छात्रावास, स्कूल से घर के रास्ते में या फिर जहां बच्चे नियमित रूप से अपने अभिभावकों से दूर जाते हों जैसे ट्यूशन, पार्क या फिर उनके खेलने जाने वाली जगहों पर होती हैं।

बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पाक्सो एक्ट बनाया था। पाक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रविधान किया गया। सख्त कानून बनने से अपराधियों को कड़ी सजा मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराध नहीं रुक रहा है। बेटियां देश और समाज का उज्ज्वल भविष्य हैं। वे पढ़ना चाहती हैं। ऐसे में अगर उनके साथ दुष्कर्म होगा और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाएगी, तो क्या वे भीतर से टूट नहीं जाएंगी? बेटियों के लिए स्कूल, छात्रावास और कालेज को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। अगर वहां भी वे असुरक्षित रहेंगी, तो कौन माता-पिता उन्हें पढ़ने के लिए यहां भेजना चाहेगा।

बच्चियों के खिलाफ हर अपराध निंदनीय है। स्कूल के छात्रावास में इस तरह के घिनौनी कुकृत्यों को अंजाम देने से समाज में नकारात्मक संदेश जाता है और ऐसी घटनाओं से पूरा देश शर्मसार होता है। भारत की बेटियां आज महज भागीदारी से आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। वे देश के समग्र विकास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में बच्चियों के साथ होने वाली इन घटनाओं पर विराम लगना चाहिए। इसके लिए बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि फिर कोई हैवान किसी मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने की हिमाकत न कर सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

देश को नुकसान पहुंचाने वाली घोषणाएं

'चिंतित करने वाले चुनावी वादे' शीर्षक से लिखे आलेख में विपक्षी दलों के देशघाती चुनावी वायदों को लेकर व्यक्त की गई ए. सूर्यप्रकाश की चिंता वाजिब है। मोदी विरोधी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की सत्ता से हटाने के लिए आइएनडीआइए बनाने के बाद अपने अलग-अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि इस गठबंधन की देशहित में न तो कोई साझा नीति है और न ही कोई एजेंडा। विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोकलुभावन चुनावी वादे किए हैं, वह देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने हर गरीब परिवार को एक लाख रुपये सालाना देने की बात की है। क्या कोई केंद्र सरकार 140 करोड़ की बड़ी आबादी वाले भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह के चुनावी वादे को निभा सकती है? निश्चित रूप से इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा, बावजूद इसके चुनावी वादों के रूप में रेवड़ियां बांटने का काम किया गया है। वामपंथी दल की देश को परमाणु अस्त्र विहीन बनाने की चुनावी घोषणा कितनी देशघाती है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। कश्मीर में अनुच्छेद-370 की पुनः बहाली का वादा करके आखिर विपक्षी दल देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में संपत्ति के पुनर्वितरण, जातिगत जनगणना, धर्म आधारित आरक्षण आदि का शिगूफा छेड़कर आखिर किस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाना चाहती है? इन प्रश्नों से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए देशहित को दांव पर लगाने का काम बदस्तूर जारी है। कदाचित इनके लिए देशहित के बजाय वोटबैंक कहीं ज्यादा जरूरी है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मतदान अनिवार्य हो

तीसरे चरण के चुनाव होने के पश्चात भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। कहा यह जाता है कि मतदान अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी है। किसी के पास अपने अधिकार को प्रयोग करने या न करने का विकल्प हो सकता है, पर कर्तव्य को पूर्ण करने के दायित्व से कोई विमुख नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग एवं शासन द्वारा यह मानकर हर मतदान केंद्र पर सारा प्रबंध किया जाता है कि हर बूथ पर शत-प्रतिशत मतदान होगा। अनेक केंद्रों तक लगभग एक तिहाई और कहीं-कहीं तो आधे मतदाता वोट देने नहीं पहुंचे, जबकि क्षेत्र विशेष में चुनाव हेतु सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। इसलिए मतदान को अनिवार्य घोषित कर दिया जाए। इससे अनेक लाभ होंगे। जब अनुपस्थित मतदाता से उसके आवास पर संपर्क किया जाएगा, तब यह बात संज्ञान में आ सकती है कि उसकी मृत्यु हो गई हो, विदेश में है, जहां से उसका आना कठिन हो, उसका विवाह हो गया हो, ट्रांसफर हो गया हो या उसने घर बदल लिया हो। इन सूचनाओं के पाने के बाद मतदाता सूची में पर्याप्त संशोधन हों पाएंगे। इनके अतिरिक्त जिसने केवल लापरवाही के कारण या पिकनिक पर जाने के कारण मतदान नहीं किया, उसको दंडित किया जाना चाहिए।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

चिंतित करते वादे

ए. सूर्यप्रकाश का आलेख 'चिंतित करने वाले चुनावी वादे' अत्यंत सटीक है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने ऐसे घोषणापत्र पेश किए हैं, जिनसे लगता है कि उन्हें देश के आर्थिक और सामाजिक हितों की कोई परवाह नहीं है। राजद जैसे क्षेत्रीय दलों जैसे ने राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। वामपंथियों का चीन प्रेम तो सब जानते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में तो हद ही कर दी। वामपंथी पार्टियां परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कह रही हैं। वामपंथी पार्टियों के अनुसार देश चला तो भारत को सामरिक दृष्टि से बेहद क्षति होगी। ऐसे ही कांग्रेस ने ऐसे वादे किए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को फिर पांचवीं से दसवीं अर्थव्यवस्था पर ले जाएंगे।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

600 से अधिक नदियां हैं भारत में, जिनमें से अधिकांश अब प्रदूषण की चपेट में हैं। सौ से अधिक नदियां अपने लंबे बहाव क्षेत्र में सूख चुकी हैं।

आजकल

भारत में लापता विदेशी नागरिकों की तलाश

देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हजारों विदेशी नागरिकों का पता लगाया जा रहा है, जिनकी वीजा अवधि खत्म हो चुकी है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा इन लापता विदेशियों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी गई है। फारनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस (एफआरआरओ) के पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही, इनके रिश्तेदारों ने लापता होने की सूचना संबंधित देशों में भारतीय दूतावास या उच्चायोग को नहीं दी है। ऐसे में यह मामला हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से खतरे की घंटी है

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रहने वाले अफ्रीकी निवासी अवैध गतिविधियों में संलग्न पाए गए हैं। फाइल

कौशल किशोर
सामाजिक मामलों के जानकार

पड़ोसी देशों से लगती सीमा अभी भी कुछ स्थानों पर खुली है, जिन्हें पार करके भारत आने वाले विदेशी नागरिकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा बांग्लादेश व म्यांमार के घुसपैठिए और शरणार्थी शामिल हैं। संसद में जुलाई 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि देश में एक करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। इनमें से 50 लाख असम में और 57 लाख बंगाल में रह रहे हैं। इस मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे किरण रिजीजू ने 2016 में संसद के पटल पर दो करोड़ बांग्लादेशी के भारत में अवैध होने का आंकड़ा पेश किया था। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कर घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच भेद स्पष्ट किया गया। इस कानून में नियम बनाने का काम भी संपन्न हो गया। यह दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले विशेष श्रेणी के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है।

बहरहाल, सुर्खियों में बने लापता विदेशी लोगों में बड़ी संख्या में नाइजीरिया और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और गोवा जैसे स्थानों पर इन अवैध प्रवासियों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। अवैध रूप से भारत में रहने वाले इन विदेशी नागरिकों में शायद ही कोई होगा, जो किसी अवैध काम-धंधे में नहीं संलिप्त हो। साथ ही वैध रूप से भारत में रहने वाले सहयोगियों की मदद के बिना इनका टिक पाना भी संभव नहीं है। विदेशी नागरिकों के रात्रि विश्राम की सूचना एफआरआरओ को देने का नियम प्रायः सभी राज्यों में लागू है। इसी तरह किसी भी अपरिचित व्यक्ति को किराये पर मकान देने पर पुलिस से सत्यापन कराने का नियम है। लेकिन दिल्ली में इन नियमों का पालन करने वाले लोग कम ही हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हजारों अवैध विदेशी नागरिकों की खोज करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं होती। इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना वसूलने के बदले आज देशप्रेम का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। देशवासियों के सहयोग के बिना यह लक्ष्य साधना संभव नहीं है।

दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां नाइजीरिया के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मकान मालिक इन लोगों से मोटी रकम ऐंठते हैं। पुलिस की मदद के बिना ये लोग पनप रहे हैं, ऐसा मानना भी मुश्किल है। नाइजीरियाई नागरिकों के इन आपराधिक कृत्यों को कहां से संरक्षण मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायिका व कार्यपालिका देशहित के बदले यदि स्वार्थ व दलीय राजनीति को वरीयता देगी, तो देश पतन के गर्त में डूब सकता है।

पिछले माह की घटना है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद किए जाने के बाद पुलिस चार नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार करती है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। एमडीएमए को मिथाइल एनीडियोक्सी मेथामफेटामाइन, एक्सटेसी और माली के नाम से जाना जाता है। बाजार में इस हार्ड ड्रग की कीमत आज 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। हर सप्ताह ऐसी खबरें सामने आ रही है। प्रायः सभी मामलों में अवैध रूप से भारत में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोग पकड़े गए हैं। विशेष कर नाइजीरियाई नागरिक। इसके एक सप्ताह पहले भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दो नाइजीरियाई नागरिकों को नोएडा से गिरफ्तार किया था, साइबर ठगी के अपराध में शामिल होने की वजह से। दो माह पहले तेलंगाना की पुलिस द्वारा एक नाइजीरियाई नागरिक को 500 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि देश भर में खपने वाले एक तिहाई बाजार को संचालित करने वाला वही था। गिरोह बना कर हेरोइन व एलएसडी समेत तमाम हार्ड ड्रग की सप्लाई देश भर में की जा रही है।

भारत ही नहीं, बल्कि इस तरह के अपराधों से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। इनमें नाइजीरियाई संगठित गिरोह के कारनामे हैरत में डालने वाली है। यह सुखद आश्चर्य का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्री व विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। जनवरी के पहले सप्ताह में दक्षिण दिल्ली के नेबसराय इलाके में नारकोटिक्स स्क्वाड बिना वीजा के अवैध तरीके से रहने वाले नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ने पहुंची थी। विरोध करने के लिए शीघ्र ही अफ्रीकी मूल के सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। इन्होंने पुलिस का घेराव किया और बदसलूकी शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस अपना बचाव कर लौट सकी। हालांकि बाद में उन लोगों को पकड़ लिया गया। एक दशक पहले गोवा में हार्ड ड्रग्स की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई अपराधी की हत्या के बाद उत्पात मचाने हेतु सैकड़ों की संख्या में जमा होने वाला गिरोह सुर्खियों में रहा। जेल जाने से बचने की इन अपराधियों की पूरी कोशिश रहती है, परंतु पकड़े जाने पर निर्वासन के बदले जेल जाने की रणनीति अपनाते हैं और निर्वासित होने पर नाम पता बदल कर लौट आते हैं।

भारत में अफ्रीकी महिलाओं से देह व्यापार कराने और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े रहस्य का पर्दाफाश भी कई बार हुआ है। तुरंत मौके पर सैकड़ों की संख्या में जमा होने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के पहुंचने का रहस्य समझ से परे नहीं।

अफ्रीका के तमाम देशों के असहाय और गरीब लोग एक अरसे से अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे हैं। इसमें नाइजीरिया दूतावास और पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसी दुरुह परिस्थिति में क्या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय लक्ष्य साध सकेगा? यह सवाल मुंह बाए खड़ा है।

भारत-नाइजीरिया के बनते बिगड़ते संबंध

दुष्यंत शर्मा
सामाजिक कार्यकर्ता

अफ्रीकी देशों से भारत में होने वाली तस्करी लगातार बढ़ रही है। नाइजीरियाई गिरोह की भूमिका हार्ड ड्रग से लेकर मानव तस्करी तक पहुंच गई है। इनके जाल में फंसे लोग तमाम तरह के अपराध में संलिप्त हैं। देश के महानगरों में बढ़ते अपराधों में नाइजीरियाई माफिया का प्रभुत्व शिखर पर पहुंचता प्रतीत हो रहा है। अफ्रीका से बढ़ते व्यापार की आड़ में बड़ी मात्रा में खतरनाक मादक पदार्थों का आयात किया जा रहा है। इन अपराधियों की हवस को पूरा करने के लिए आज महिलाओं की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। केन्या की एक महिला का केस पांच साल पहले सुर्खियों में था। संबंधित माफिया ने इसे नौकरी के बहाने भारत बुला कर देह और मादक पदार्थों के व्यापार में धकेल दिया था।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 21 प्रतिशत भागीदारी के साथ नाइजीरिया शीर्ष व्यापारिक साझेदार साबित होता है। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 11.8 अरब डालर था। यह मुख्य रूप से तेल निर्यातक देश है, जो वर्ष 1971 से ही तेल उत्पादक कार्टेल ओपेक का सदस्य है। अफ्रीकी संघ से भारत के आयात का करीब 61 प्रतिशत हिस्सा ईंधन है। इसके अलावा, धातु, कीमती पत्थरों, अयस्कों और कांच का भी आयात करता है। आज भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 30 अरब डालर का निवेश कर रखा है। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है।

अफ्रीका के पश्चिमी भाग में 2600 मील लंबी नाइजर नदी के बेसिन में फैला नाइजीरिया भी लंबे अरसे तक ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत ने नाइजीरिया को 1960 में मिली आजादी से दो साल पहले लागोस में कूटनीतिक हाउस शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में नाइजीरिया के राष्ट्रपति 1983 में मुख्य अतिथि रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में वहां के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मंच पर दोनों देशों के बीच संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। ठीक इसी तरह लगातार नाइजीरियाई गिरोह का अपराध भी बढ़ रहा है।

इन अपराधियों की सफलता के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये लोग आपस में अफ्रीकी बोलियों का ही प्रयोग करते हैं और दूसरे लोगों को अपने गैर कानूनी धंधे में शामिल भी नहीं करते हैं। देश भर में रेव पार्टियों के आयोजकों से इनके तार जुड़े हुए हैं। खतरनाक मादक पदार्थों की आपूर्ति इनके द्वारा की जा रही है। भारत में अनेक स्थानों पर निरंतर इनके कारनामे सामने आते रहते हैं। इनके कारनामों की वजह से नाइजीरिया के सज्जन लोग किसी और अफ्रीकी देश को अपना बताने को मजबूर हैं। अफ्रीकी भाषाओं में संवाद करने वाले लोगों का भारत में एक सक्रिय समूह आल इंडिया नाइजीरियन स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी एसोसिएशन (एंस्का) कहलाता है। केवल नाम से ही यह नाइजीरियाई है। सही मायनों में यह तमाम अफ्रीकी देशों का एक ऐसा नेटवर्क है, जो भारत में सक्रिय है। संगठित अपराधों में लिप्त प्रायः सभी अफ्रीकी इसके सदस्य होते हैं। ऐसे में यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि नाइजीरियाई दूतावास की मदद के बिना इन्हें सफलता नहीं मिल सकती है। परंतु दूतावास के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ कर कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए आज की मांग है कि इस तरह के लोगों और नेटवर्क पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिए, ताकि इस गिरोह को समाप्त किया जा सके।

खरी-खरी

वोटर के दुख पुराण

रेखा शाह आरबी

चुनाव के समय वोटर ही चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। सारी पार्टियां घूम-फिर कर वोटर की भांति-भांति से परिक्रमा करती हैं। उसकी चिंता हर पार्टी करती है। कोई पार्टी चाह कर भी चुनाव के समय उसे अनदेखा करके चुनावी रणभूमि में सही सलामत नहीं रह सकती है। वोटर का महत्व इसी से पता चलता है कि यदि वह चाह ले तो नेताओं की कुर्सी एक पल में उनसे रूठ कर चली जाती है। यदि वह चाह ले तो छप्पर फाड़ के वोट बरसता है। माफ कीजिएगा... पहले छप्पर फाड़ के धन बरसता था। लेकिन आजकल यह कहावत सटीक नहीं है, आजकल इनके ऊपर छप्पर फाड़ कर वोट बरसता है। उसके पास ही नोट भी बरसता है, इसीलिए अब नई कहावत बनाई है कि छप्पर फाड़ कर वोट बरसना। लेकिन आजकल वोटरों की जान भी सांसत में है। हर नेता अपने तरीके से लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है।

रामभरोसे एक ऐसे ही सरल सीधे साधे वोटर हैं। हर पार्टी रामभरोसे को लुभा जाती है। तो कभी उसे पार्टियां कंफ्यूज कर देती हैं। रामभरोसे को कंफ्यूज करने के लिए दूसरी पार्टी नए-नए तरीके से उसके सब्र की आजमाइश लेती हैं। वोटर रामभरोसे का यह हाल है कि मानो वह किसी आइसक्रीम के ठेले पर खड़ा है। उसे हर आइसक्रीम उछल-उछलकर कह रही है, मेरा स्वाद अच्छा है, मुझे खा लो, मेरा स्वाद अच्छा है, मुझे खा लो। रामभरोसे की मुश्किल यह है कि उसे एक ही आइसक्रीम खानी है। ज्यादा खाने का आप्शन नहीं है। तो वह दुविधा में है किस आइसक्रीम को वह चुने। आइसक्रीम को वह पहले चेक भी नहीं सकता है। देखने में सारी आइसक्रीम अपनी खूब डेंटिंग-पेंटिंग करके उछल कूद मचा रही हैं। वह यह भी नहीं जानता कि कौन सी आइसक्रीम मीठी निकलेगी और कौन सी फीकी।

लेकिन एक आइसक्रीम तो खानी ही पड़ेगी। अब सारा कुछ उसके नसीब पर है कि उसके भाग्य में क्या मिलेगा? आखिर सब कुछ एक ही में मिल तो नहीं सकता, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, तो कोई मीठे का पूरी तरह ख्याल नहीं रखेगा, तो कोई कितना ठंडा रहना चाहिए इसका ख्याल नहीं रखेगा।

पोस्ट

परिवारवादी पार्टियों को बहन मायावती जी से सीखना चाहिए और अपरिपक्व लड़कों को हटाकर परिपक्व नेताओं को अपना नेतृत्व सौंपना चाहिए।
आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

सैम पित्रोदा को हर भारतीय में अफ्रीकी, अरबी, यूरोपीय और चीनी दिख गया। किसी भारतीय में भारतीय नहीं दिखा।
जगदीश भाटिया@jagdish

सैम पित्रोदा ने यह तय कर लिया है कि वह किसी भी सूरत में नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर ही मानेंगे।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

आखिरकार मुझे खुद के अफ्रीकियों-अरबों जैसे दिखने का रहस्य पता चल गया। धन्यवाद सैम पित्रोदा।
विक्रम संपत@vikramsampath

प्रधानमंत्री यह सही कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि वे अपना और साथ ही देश का भविष्य कैसे बेहतर करें।
उमर गाजी@OmerGhazi2

देश के मुस्लिमों को तय करना होगा कि वे महज एक वोट बैंक बने रहना चाहते हैं या फिर भारत के जागरूक नागरिक?
आमना बेगम अंसारी@Amana_Ansari

सदगुरु शरण
संपादक, नईदुनिया, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश डायरी

भाजपा डाल-डाल तो कांग्रेस पात-पात

भाजपा के किसी छोटे-बड़े नेता के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि पार्टी का बेहद मजबूत राजनीतिक किला मानी जाने वाली इंदौर लोकसभा सीट के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन वापस करवाने की क्या जरूरत थी और इससे भाजपा को क्या लाभ मिला? इसी सीट से आठ बार सांसद रहीं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी इस सवाल का जवाब तलाश रही हैं। उन्हें हैरत है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा क्यों किया। इंदौर में ताई की संज्ञा से बेहद लोकप्रिय सुमित्रा महाजन पार्टी की वरिष्ठतम नेता हैं, यद्यपि इस प्रकरण की जानकारी उन्हें समाचार माध्यमों से ही मिली। स्पष्ट है कि इस आपरेशन के सूत्रधार नेताओं ने सारे नंबर स्वयं लेने के लिए ताई जैसी वरिष्ठ नेता को भी विश्वास में नहीं लिया। इस प्रकरण के सूत्रधार माने जाने जा रहे वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने स्वयं यह कदम उठाया। इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं।

बहरहाल, अक्षय कांति बम का भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने जाना, वहां से सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचकर भगवा दुपट्टा धारण करना और इसके बाद लगातार कैलाश विजयवर्गीय के साथ घूमना असली कहानी स्वयं बयां कर देता है। इंदौर के भाजपा नेताओं की इस आक्रामकता को केंद्रीय नेतृत्व ने किस तरह लिया, भविष्य में पता चलेगा, यद्यपि शहर के भाजपा समर्थकों ने भी इसे पसंद नहीं किया। सब यही सवाल कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी। इंदौर में भाजपा हार-जीत के अंतर का रिकार्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन वापस करवाने से क्या हासिल हुआ? यह उल्लेख प्रासंगिक है कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी (इस बार भी वही उम्मीदवार हैं) ने यह सीट करीब साढ़े पांच लाख वोटों के अंतर से जीती थी।

कैलाश विजयवर्गीय। फाइल

जीतू पटवारी। फाइल

यह तो भाजपा की बात हुई। अब जरा कांग्रेस के कैंप पर नजर डालते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने गृह नगर में कांग्रेस की इस फजीहत पर कई दिन बिलबिलाते रहे। हर कोई उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहा है कि उन्होंने मनमाने ढंग से कई अच्छे दावेदारों को नजरअंदाज करके अक्षय कांति बम जैसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया जिसने देशभर में पार्टी की साख बिगाड़कर रख दी। अब जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार 'नोटा' होगा। इस निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ता भी भौचक हैं। लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में इससे अधिक नकारात्मक फैसला क्या हो सकता है कि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतदाताओं से नोटा पर वोट देने की अपील करे। भाजपाइयों की तरह अब कांग्रेस कार्यकर्ता भी सवाल कर रहे हैं कि इस फैसले का क्या अर्थ है और इससे पार्टी को क्या लाभ होगा?

मतदान में नोटा अंतिम विकल्प होता है जिसका आशय यह है कि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट देने लायक नहीं मानता। देश के चुनावी इतिहास और नोटा विकल्प स्थापित होने के बाद यह पहला अवसर है जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, वह भी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल ने मतदाताओं से नोटा विकल्प चुनने की अपील की है। भाजपा उम्मीदवार के प्रति कांग्रेस का परहेज स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव मैदान में मौजूदा 12 निर्दलीय उम्मीदवारों में एक भी ऐसा नहीं है जिसे कांग्रेस अपना समर्थन दे सके? इससे पहले खजुराहो संसदीय सीट पर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद होने के बाद गठबंधन ने एक ऐसे ही उम्मीदवार का चयन करके समर्थन की घोषणा की थी, लेकिन इंदौर में कांग्रेस को नोटा पसंद आया। परिणाम आने पर पता चलेगा कि कांग्रेस का यह कदम इंदौरियों को रास आया या नहीं।

कांग्रेस द्वारा नकारात्मकता प्रदर्शित करने का यह पहला अवसर नहीं है। मौजूदा चुनाव की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में दो बड़े कांग्रेस नेताओं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने घोषणा की थी कि वे अपनी लोकसभा सीट पर 384 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन करवाएंगे, ताकि चुनाव आयोग इन सीटों पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिये मतदान करवाने पर बाध्य हो जाए। इस घोषणा ने चुनावी माहौल में खासी सनसनी पैदा की, यद्यपि दोनों नेता अपने कार्यकर्ताओं को नामांकन करने के लिए तैयार करने में पूरी तरह विफल रहे। जानकार मानते हैं कि इंदौर में भाजपाइयों की अति आक्रामकता से कांग्रेस को ऐसा मुद्दा मिल गया था जिसे तूल देकर पार्टी भाजपा को कठघरे में खड़ा कर सकती थी, पर इसे समझने के बजाय जीतू पटवारी एंड कंपनी ने भाजपा की ही तर्ज पर पलटवार करते हुए नोटा को उम्मीदवार घोषित करके यह मौका गंवा दिया। भाजपा नेताओं के आचरण पर छिड़ी बहस जीतू पटवारी के इस कदम के बाद धीमी पड़ गई है और लोग यह बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा नोटा का समर्थन कितना नैतिक है?

जागरण जनमत कल का परिणाम

दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने वाली स्त्रियों को सजा सुनाने से ऐसे मामलों में कमी आएगी?

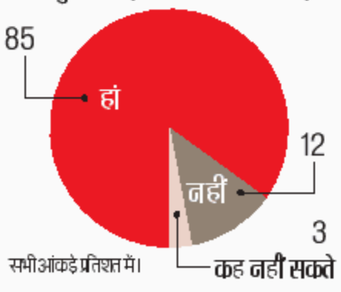

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मायावती का यह कहना सही है कि आकाश आनंद में परिपक्वता की कमी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जैसे ही उगने लगे थोड़े-थोड़े पंख,
तुरत भतीजे को लगा एक जोर का डंक।
एक जोर का डंक बुआ जी ने ही मारा,
चलो बेटा आकाश पढ़ो घर बैठ पहाड़ा।
माया जी बर्दाश्त किसी को करतीं कैसे,
लिये सभी पद छीन दिए थे उनको जैसे।
- ओमप्रकाश तिवारी

पानी के अपव्यय पर नियंत्रण

पेयजल शुद्धता रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 55 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों के लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पेयजल में अनेक घातक रसायन मिले हुए हैं

मंथन

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

जल जीवन तत्व है, इसलिए इसे औषधियों की औषधि और अमृत कहा गया है। यह प्रकृति-पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होने के साथ जड़-चेतन की निर्मिती का मूल भी है। जिस प्रकार अनुपातिक दृष्टि से पृथ्वी पर भूमि की अपेक्षा जल की अधिकता है, उसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी जल की अधिकता है। जल की इस मात्रा का कम अथवा अधिक होना जीवन के लिए संकट है। इसलिए जल के संरक्षण-संवर्धन हेतु जल जागरण अभियान की आवश्यकता है।

वर्ष 2019 का ही एक समाचार बताता है कि 80 प्रतिशत ग्रामीण भारत में नल से जल नहीं है। देश के 60 प्रतिशत जिले ऐसे हैं, जहां भूजल अतिदोहित है और गुणवत्ता बेहद खराब है। ऐसे में बड़ी चुनौती यह भी है कि नदियां, कुएं, तालाब, ट्यूबवेल एवं हैंड पंप आदि प्रमुख जल स्रोत गंभीर प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। अनेक स्थानों पर नदियां दम तोड़ रही हैं, भूजल स्तर घट रहा है। भारत में छोटी बड़ी लगभग 600 नदियां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रदूषण की शिकार हैं। सैकड़ों सूख चुकी हैं और सैकड़ों सूखने के कगार पर हैं। हाल ही में बेंगलुरु में जल संकट भयावह हो गया, जिसके कारण स्कूल-कालेज कई दिनों के लिए बंद करने पड़े। कई कार्यालयों को वर्क फ्राम होम मोड में संचालित करना पड़ा। झारखंड में वन, नदियां, झरने, झील, तालाब और कई बड़े-बड़े डैम होने के बावजूद भूगर्भ जलस्तर पाताल छू रहा है। कई नदियां सूख चुकी हैं, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर काफी गिर चुका है।

नलों के माध्यम से घरों तक आने वाले पानी की बर्बादी रोकने के लिए सजग होना पड़ेगा। प्रतीकात्मक

चिंताजनक यह है कि ऐसी सहायक नदियां लगा लगातार सूख रही हैं। ये नदियां औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन एवं अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन समाचार आते हैं, तदुपरांत भी प्रदूषण, अतिक्रमण और खनन जारी है। अतिक्रमण के कारण नदियां अविरल प्रवाह के संकट से जूझ रही हैं। विभिन्न परियोजनाओं एवं अवैध निर्माण से उनके बहाव में अवरोध आ रहा है। हमें यह समझना होगा कि नदी के बहाव क्षेत्र में रेत, पत्थर एवं अनेक प्रकार की वनस्पतियां नदी के जीवन को सुचारु करने में सहायक होती हैं। उनका खनन, नदी की हत्या का ही प्रयास है। घरेलू प्रयोग, खेती, औद्योगिक उपयोग एवं निर्माण आदि के लिए भूजल पर निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है।

भूजल दोहन करने वाले राज्यों में पंजाब 76 प्रतिशत, राजस्थान 66 प्रतिशत, दिल्ली 56 प्रतिशत और हरियाणा 54 प्रतिशत के साथ सबसे आगे हैं। चिंताजनक यह है कि जिस अनुपात में भूजल दोहन हो रहा है, उस अनुपात में वह वापस रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वर्षा जल का लगभग 6-7 प्रतिशत ही हम संग्रह कर पाते हैं। हमें यह समझना होगा कि पहाड़, वन क्षेत्र, नदियां एवं जलस्रोत पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मार्च 2021 में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय लगभग सात करोड़ से अधिक घरों को नल और जल उपलब्ध करवा चुका है। देश के तीन राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शत प्रतिशत नल एवं स्वच्छ जल युक्त हो चुके हैं, लेकिन चुनौती जल की उपलब्धता की है। यदि नदियों एवं प्राकृतिक स्रोतों में जल ही न होगा, तो नल से घरों तक कैसे पहुंचेगा।

ध्यान रहे महानगरों की हरियाली और भिन्न-भिन्न प्रकार के विकास का अस्तित्व जल पर ही निर्भर है। जल के अभाव में किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। जल जागरण के व्यापक अभियान से जन जागरूकता आवश्यक है। छोटे-बड़े अनेक स्थानों पर पाइप लाइनों से पेयजल व्यर्थ बहता रहता है। घरों में सफाई के लिए, गाड़ियों की धुलाई के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग अंधाधुंध जारी है। एक अनुमान के अनुसार एक जींस तैयार करने के लिए लगभग दो हजार लीटर पानी की खपत होती है। क्या हमें अपनी जीवन शैली और खेती की पद्धति में भी बदलाव नहीं करने चाहिएं? वर्षा की एक-एक बूंद बचाने के लिए अमृत सरोवरों का निर्माण, कुएं, बावड़ी आदि का पुनरुद्धार आवश्यक है। आज यह भी नितांत आवश्यक है कि छोटे बड़े सभी शिक्षण संस्थानों में जल शिक्षा और साक्षरता अनिवार्य की जाए। यह सत्य है कि हम जल बना तो नहीं सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। जल संकट से उबरने के समाधान हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा में उपलब्ध हैं। जल संरक्षण-संवर्धन सभी का संस्कार बने, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान है, आइए जल उत्सव मनाएं। ध्यान रहे जल है, तो ही जीवन है। जल है, तो ही कल है। इसलिए बेहतर कल के लिए और जीवन के लिए जल जागरण हमारा विचार और व्यवहार बनना आवश्यक है।

****